राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण गुरुवार 20 अगस्त 2026 वर्ष-9,अंक-198 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

मिड-डे मील में नमक की जगह परोस दिया डिटर्जेंट पाउडर, 40 बच्चे बीमार

दौड़े-दौड़े अस्पताल पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार

पटना।

बिहार के नालंदा जिले के पारसी मिडिल स्कूल में मिड-डे मील के दौरान भयावह लापरवाही सामने आई है। नमक की जगह डिटर्जेंट पाउडर परोसे जाने से करीब 40 स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए। खाना खाने के तुरंत बाद बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में बिहार शरीफ़ मॉडल अस्पताल ले जाया गया। स्कूल के शिक्षक ने बताया कि मिड-डे मील की आपूर्ति किसी दूसरे स्कूल से हुई थी। सोयाबीन की सब्ज़ी में नमक कम होने पर जब छात्रों ने नमक मांगा, तब गलती से डिटर्जेंट पाउडर दे दिया गया। छात्रों ने अनजाने में डिटर्जेंट पाउडर खा लिया, जिसके तुरंत बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। घटना की खबर सुनकर चिंतित माता-पिता बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। नालंदा के सिविल सर्जन डॉ. जय प्रकाश सिंह सहित कई डॉक्टर बच्चों के इलाज में जुट गए। डॉ. सिंह ने आश्वस्त किया कि सभी बच्चे सुरक्षित हैं और उनकी हालत पर लगातार नज़र रखी जा रही है। वहीं बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी अस्पताल पहुंचे और प्रभावित छात्रों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल प्रशासन को बच्चों का उचित इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और गंभीर लापरवाही के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया। मंत्री ने मिड-डे मील में बरती जाने वाली सावधानी पर भी ज़ोर दिया। जिला प्रशासन अब इस बात की जांच कर रहा है कि खाने की सामग्री के पास डिटर्जेंट पाउडर कैसे रखा गया और यह गलती कैसे हुई। अधिकारियों द्वारा मिड-डे मील की तैयारी और आपूर्ति व्यवस्था की भी गहन जांच की जाएगी। फिलहाल, सभी का ध्यान बीमार बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने पर केंद्रित है।

डीजेबी टेंडर घोटाले में एसीबी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार

-वित्तीय जांच में रिश्वत और कमीशन के पैसे के लेनदेन की शृंखला उजागर

नई दिल्ली।

दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आधुनिकीकरण में अनियमितताओं और आपराधिक साजिश के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ व पूर्व आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और तीन निजी संस्थाओं और कंपनियों के मालिकों नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुरर एवं पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी प्रमुख एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त विक्रमजीत सिंह के बयान के मुताबिक ये गिरफ्तारियां एफआईआर के बाद की गईं थीं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पीएस भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जीएनसीटीडी में पंजीकृत है। जांच में सामने आया कि एसटीपी टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी शर्तों और नियमों में जानबूझकर फेरबदल किया गया था। टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की गईं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए और एक खास निजी टेक्नोलॉजी प्रदाता कंपनी 'मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। जांच अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित पायलट स्टडी को पूरा न करना, तकनीकी मापदंडों में बदलाव और उपचारित पानी के जरुरी मानकों को हटाना जैसी अनियमितताएं पाई गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला है कि टेंडर की शर्तें तय करने और संशोधन जारी करने में निजी व्यक्तियों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियमित साठगांठ थी, ताकि टेंडर केवल पसंदीदा कंपनी को ही मिले। वित्तीय जांच में रिश्वत और कमीशन के पैसे के लेनदेन की पूरी श्रृंखला उजागर हुई है।

सरकारी ठेकों में छोटे कारोबारियों और छोटे उद्योगों को मिलेगी सहायता

-केंद्र सरकार बैंक गारंटी और अमानत राशि में देगी छूट?

नई दिल्ली ।

सरकारी ठेकों में छोटे कारोबारियों और छोटे उद्योगों को बड़ी राहत देने की तैयारी है।

केंद्र सरकार सरकारी टेंडर में परफॉर्मेंस बैंक गारंटी और अमानत राशि की अनिवार्यता को कम करने पर विचार कर रही है। इसका उद्देश्य छोटे कारोबारियों पर आर्थिक बोझ घटाना और उन्हें सरकारी कामों में ज्यादा अवसर देना है। मौजूदा व्यवस्था में ठेका मिलने के बाद कारोबारियों को अपनी रकम का एक हिस्सा बैंक गारंटी के तौर पर रखना पड़ता है। इससे छोटे कारोबारियों की कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है। प्रस्ताव पर एमएसएमई मंत्रालय और उद्योग संवर्धन विभाग के बीच चर्चा चल रही है। माना जा रहा है कि नियमों में बदलाव होने से छोटे उद्योगों को कारोबार बढ़ाने में मदद मिलेगी और सरकारी ठेकों में उनकी भागीदारी भी बढ़ सकती है। सरकार का जोर छोटे कारोबारियों के लिए प्रक्रिया आसान बनाने पर है।

एनटीए का बड़ा फैसला-परीक्षा सुरक्षा के लिए 600 विशेषज्ञ हटाए

- केंद्रीय मंत्री को बताया, पूरी टीम में बदलाव

नई दिल्ली ।

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने अपनी परीक्षाओं की सुरक्षा और मजबूती सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। एजेंसी ने अपनी पूरी परीक्षा टीम में व्यापक बदलाव कर दिए हैं, जिसके तहत अब तक पेपर सेट करने में मदद कर रहे 600 विशेषज्ञों को हटाकर नए एक्सपर्ट्स को शामिल किया जा रहा है। यह कदम शिक्षा मंत्री प्रल्हाद जोशी द्वारा बुलाई गई बैठकों के बाद उठाया गया है। केंद्रीय मंत्री ने निर्देशों में कहा कि परीक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा और संबंधित बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराए जाएं।

एनटीए, जो जेईई-मैंस, नीट-यूजी, क्लेट और यूजीसी-नेट जैसी प्रमुख परीक्षाओं का संचालन करती है, ने अपनी प्रक्रियाओं को अधिक पुख्ता बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। एनटीए के डायरेक्टर जनरल अभिषेक सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इन उपायों से अवगत कराया। अब परीक्षा के पेपर की जांच-पड़ताल को और मजबूत करने के लिए एक चार-स्तरीय प्रश्न-पत्र जांच प्रणाली लागू की जाएगी।

अगले दो से तीन हफ्तों में 20 से 25 नए अधिकारियों को भी एजेंसी में शामिल किया जाएगा, और भविष्य की नियुक्तियों पर विचार हो रहा है।

सुरक्षा को प्राथमिकता देकर एनटीए अपने वर्तमान ओखला कार्यालय को मिंटो रोड स्थित एक नए, अधिक सुरक्षित परिसर में स्थानांतरित करेगा। नई जगह पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की टीमों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जोशी ने एनटीए को अपनी सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का ऑडिट करने और एक महीने के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश दिया है।

सीएम विजय का ऐलान-हर विधायक को मिलेगी नई कार

विधायकों की मांग पर टीवीके सरकार का फैसला, क्षेत्र में दौरे और विकास कार्यों की निगरानी में मिलेगी मदद

चेन्नई।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख थलपति विजय ने राज्य के सभी विधायकों को यात्रा के लिए नई कार उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लगातार दौरे करने पड़ते हैं और जनता की समस्याओं तथा जरूरतों का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र में रहना जरूरी है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त लॉजिस्टिक्स और वाहन सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सरकार का यह फैसला विधानसभा में विधायकों के लिए वाहनों और जरूरी लॉजिस्टिक्स की सुविधा का मुद्दा उठाए जाने के बाद आया है।

वीसीके विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में कहा था कि यदि विधायकों को जरूरी संसाधन और वाहन उपलब्ध नहीं होंगे तो वे अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे।

उन्होंने सरकार से विधायकों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री विजय ने विधायक के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए सभी विधायकों के लिए नई कार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहन सुविधा मिलने से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे और जनता से सीधे संवाद के साथ-साथ विकास कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। जनता से संपर्क में आसानी होगी मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार की ओर से सभी विधायकों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आने-जाने वाले विधायकों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है।

विधायक नियमित रूप से अपने क्षेत्र का दौरा कर सकेंगे और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा अन्य स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित विभागों के साथ उनका समाधान कराने में तेजी ला सकेंगे।

विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में अपने क्षेत्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए वाहनों को जरूरी सुविधा बताया था।

पुलिस द्वारा आरोपियों के वीडियो-फोटो पोस्ट करना निजता के अधिकार का उल्लंघन?

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से मांगा जवाब

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर केंद्र और कई राज्य सरकारों से जवाब मांगा है। इस याचिका में पुलिस पर आरोप है कि वे गिरफ्तार आरोपियों के वीडियो अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट करके उनके निजता और सम्मान के अधिकार का उल्लंघन करती हैं, जिससे उन्हें सार्वजनिक अपमान और मीडिया ट्रायल का सामना करना पड़ता है। जनहित याचिका दायर करने वाले हेमेंद्र पटेल ने वकील गोपाल शंकरनारायणन के जरिए चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी मोहना की बेंच को बताया कि अक्सर पुलिस अपने आधिकारिक हैंडल पर ऐसे सोशल मीडिया पोस्ट करती है जिनमें आरोपी हथकड़ी पहने, रस्सियों से बंधे, डंडों से पीटे जाते हुए और दूसरे तरह के दुर्व्यवहार का शिकार होते हुए दिखते हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि जब आरोपियों को सबके सामने घुमाया जाता है और उन्हें चलने में मुश्किल होती है, तो यह कस्टडी में टॉर्चर का देता है। आरोपियों की पहचान जाहिर करने से मीडिया ट्रायल होता है और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की पवित्रता पर असर पड़ता है, जो क्रिमिनल ट्रायल में सबूत का अहम हिस्सा होती हैं। बेंच ने केंद्र, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, क्योंकि याचिका में चंडीगढ़ पुलिस मॉडल को लागू करने की मांग की गई थी।

क्या मोदी सरकार ने पीएम रहमान को डाला है धर्मसंकट में?

नई दिल्ली आने के न्योते पर अब तक चुप्पी, ढाका बोला- अनुकूल माहौल जरूरी

नई दिल्ली।

बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत जारी है, लेकिन अब तक उनकी ओर से नई दिल्ली आने पर सहमति नहीं बनी है। दरअसल तारिक रहमान इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद भारत ने उन्हें नई दिल्ली आने का न्योता दिया, लेकिन उन्होंने अपने पहले विदेशी दौरे के लिए भारत के बजाय मलेशिया को चुना। इसके बाद उन्होंने चीन की यात्रा भी की। अब भारत आएंगे या नहीं संशय बरकरार है। भारत ने उनके विदेश दौरों और शेख हसीना के भारत में रहने जैसे तमाम घटनाक्रमों के बावजूद बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में अतिथि के तौर पर शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस न्योते पर भी ढाका की ओर से अभी तक अंतिम सहमति नहीं दी गई है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को कहा था कि तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा को लेकर कई सप्ताह से दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है। शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिगड़ा माहौल? बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के साथ रिश्तों के मौजूदा माहौल को लेकर भी चिंता जताई है। मंत्रालय के प्रवक्ता ए.के.एम. शाहिदुल करीम ने कहा कि 5 अगस्त को दिल्ली के फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब में अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से दोनों देशों के संबंधों का माहौल प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना जरूरी है।

ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को नई दिल्ली बुलाने के लिए लगातार प्रयास क्यों कर रहा है? इस पर जानकार कहते हैं कि इस समय भारत के पास पड़ोसी देश के साथ संवाद बनाए रखने के अलावा ज्यादा विकल्प नहीं हैं। विशेषज्ञों की मानें तो दोस्त बदले जा सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। इसलिए भारत बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संपर्क और संवाद बनाए रखने की कोशिश जारी है।

वर्तमान हालात में भारत के लिए तारिक रहमान सरकार के साथ संवाद कायम रखना रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं, ढाका की ओर से यात्रा के लिए अनुकूल माहौल की शर्त सामने आने से यह संकेत मिलता है कि दोनों देशों के रिश्तों में अभी कई संवेदनशील मुद्दे मौजूद हैं।

चीन में सुबह-सुबह कांपी धरती लोगों में दहशत

5.6 तीव्रता से आया भूकंप

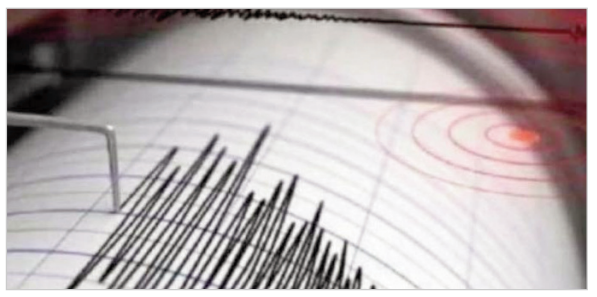

बीजिंग।

चीन के उत्तर-पश्चिमी इलाके में बुधवार सुबह 5.6 तीव्रता के भूकंप से धरती हिल गई। जैसे ही धरती हिलने का अहसास हुआ लोग घरों से बाहर भागे और सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे।

हालांकि इस घटना से किसी तरह का कोई जानमाल का नुकसान होने की खबर नहीं है।

चीन भूकंप नेटवर्क केंद्र के मुताबिक भूकंप छिंगहाई प्रांत के हैशी प्रीफेक्चर में सुबह करीब 5 बजकर 36 मिनट पर आया। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर लगभग 10 किलोमीटर की गहराई में दर्ज किया गया। इसका केंद्र 37.81 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 95.63 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बताया गया है।

पटना में राजभवन मार्च के दौरान तेजस्वी यादव हिरासत में

पटना।

बिहार में बुधवार को राष्ट्रीय जनता दल के राजभवन मार्च के दौरान पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को हिरासत में ले लिया। आरजेडी ने छात्रों और युवाओं से जुड़े मुद्दों, पेपर लीक तथा बेरोजगारी के खिलाफ यह मार्च निकाला था। पार्टी ने पिछले महीने सिवान में छात्र प्रदर्शन के दौरान कथित तौर पर एके-47 के इस्तेमाल को लेकर भी सरकार से जवाब मांगा।

तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण तरीके से छात्रों के मुद्दे उठाने के लिए मार्च कर रही थी, लेकिन सरकार इससे डर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी बेरोजगारी कम करने, पेपर लीक रोकने और परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग को लेकर अपना संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि वे जेल जाने से नहीं डरते और छात्रों के अधिकारों की आवाज उठाते रहेंगे। आरजेडी सांसद मीसा भारती को भी पुलिस ने हिरासत में लिया। उन्होंने कहा कि बिहार के छात्र अपने अधिकारों के लिए जेल जाने को तैयार हैं।

उन्होंने सिवान के जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित करने की मांग दोहराई और कहा कि पार्टी तथा बिहार की जनता अपने मुद्दों से पीछे नहीं हटेगी।

मार्च में आरजेडी सांसदों, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता शामिल हुए।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

डोनाल्ड ट्रंप को क्यों भा गया भारतीय निर्वाचन आयोग?

(लेखक- सौरभ वार्ष्णेय)

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के साथ टैरिफ पर टैरिफ खेल रहे थे अचानक युद्व छोड़कर भारत की चुनाव व्यवस्था और मतदाता पहचान प्रणाली यानी भारतीय निर्वाचन आयोग को पंसद कर रहे हैं। ज्ञात रहे कि हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव व्यवस्था की तुलना भारतीय चुनाव मतदाता पहचान प्रणाली से की है। ट्रंप ने भारत के विशाल चुनावी तंत्र, फोटो पहचान-पत्र की व्यवस्था और सीमित डाक मतपत्र व्यवस्था को अमेरिका के लिए उदाहरण के रूप में पेश किया। उन्होंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार से कथित बातचीत का भी उल्लेख किया, हालांकि इस बातचीत का स्वतंत्र सार्वजनिक रिकॉर्ड अभी स्पष्ट रूप से सामने नहीं आया है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान केवल भारत की चुनाव प्रणाली की प्रशंसा भर नहीं है। इसके पीछे अमेरिकी राजनीति, मतदाता पहचान, चुनावी पारदर्शिता और आगामी अमेरिकी मध्यावधि चुनावों की राजनीति भी दिखाई देती है। सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है कि आखिर भारत की चुनाव व्यवस्था में ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति को आकर्षित कर रहा है? भारत का निर्वाचन आयोग कोई सामान्य प्रशासनिक संस्था नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत उसे संसद, राज्य विधानसभाओं तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की देखरेख, निर्देशन और नियंत्रण का संवैधानिक दायित्व प्राप्त है। निर्वाचन आयोग स्वयं भी इसे स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में वर्णित करता है।

भारत में चुनाव कराना अपने आप में दुनिया का एक असाधारण प्रशासनिक अभियान है। करोड़ों मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचाना, मतदाता सूची तैयार करना, पहचान सुनिश्चित करना, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए समान अवसर बनाए रखना तथा परिणामों को घोषित करना-यह पूरा तंत्र विशाल स्तर पर काम करता है। ट्रंप ने भारत के हालिया आम चुनाव में लगभग 646 मिलियन मतदाताओं का उल्लेख करते हुए भारतीय फोटो पहचान व्यवस्था को अमेरिका के संदर्भ में उपयोगी बताया। यहीं से भारत और अमेरिका के चुनावी मॉडल में एक महत्वपूर्ण अंतर सामने आता है। अमेरिका में चुनावों का संचालन काफी हद तक राज्यों के स्तर पर होता है और नियमों में राज्यवार अंतर दिखाई देता है। इसके विपरीत भारत में निर्वाचन आयोग एक केंद्रीय संवैधानिक संस्था के रूप में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनावों के लिए व्यापक अधिकार रखता है। ट्रंप की नजर में यही केंद्रीकृत चुनाव प्रबंधन एक आकर्षक मॉडल हो सकता है। ट्रंप की टिप्पणी को समझाने के लिए अमेरिकी राजनीति को समझना आवश्यक है। अमेरिका में मतदाता पहचान और नागरिकता सत्यापन लंबे समय से राजनीतिक बहस का विषय रहे हैं। ट्रंप लगातार यह तर्क देते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में पहचान और नागरिकता की पर्याप्त जांच होनी चाहिए।इसी पृष्ठभूमि में उन्होंने भारत का उदाहरण दिया। उनका उद्देश्य केवल भारत की प्रशंसा करना नहीं, बल्कि अमेरिकी मतदाता पहचान कानूनों के पक्ष में राजनीतिक समर्थन जुटाना भी है। ट्रंप प्रशासन के माध्यम से मतदाता पंजीकरण में नागरिकता प्रमाण और देशव्यापी फोटो पहचान जैसे प्रावधानों पर जोर दे रहा है।इसलिए यह कहना अधिक उचित होगा कि ट्रंप को भारत इसलिए भा रहा है क्योंकि भारतीय चुनाव प्रणाली का एक हिस्सा उनके घरेलू राजनीतिक एजेंडे के अनुकूल दिखाई देता है।यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है-क्या ट्रंप वास्तव में भारतीय चुनाव प्रणाली को अमेरिकी चुनाव व्यवस्था का आदर्श मानते हैं या वे भारत का उदाहरण अपनी घरेलू राजनीति में एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं?

भारत की चुनाव व्यवस्था की अपनी खूबियां हैं। लेकिन भारत भी पूर्ण व्यवस्था होने का दावा नहीं कर सकता। मतदाता सूची में नाम जुड़ने या हटने, पहचान संबंधी समस्याओं, चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता और निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता को लेकर समय-समय पर राजनीतिक विवाद उठते रहे हैं। हाल के वर्षों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण को लेकर भी तीखी राजनीतिक बहस हुई है। 2026 में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्ष और नागरिक समूहों ने सवाल उठाए हैं, जबकि निर्वाचन आयोग ने अपने संवैधानिक अधिकारों के भीतर काम करने का पक्ष रखा है। इस मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय में भी निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची तैयार करने की शक्तियों को लेकर प्रश्नों पर विचार हुआ है।इसलिए ट्रंप की प्रशंसा को भारत की चुनाव प्रणाली के लिए अंतिम प्रमाणपत्र मान लेना उचित नहीं होगा।किसी भी चुनाव की सफलता केवल इस बात से तय नहीं होती कि कितने लोगों ने मतदान किया। असली सफलता तब होती है जब हारने वाला उम्मीदवार और उसके समर्थक भी परिणाम को स्वीकार करें।

भारत में निर्वाचन आयोग की भूमिका इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संविधान ने उसे चुनावी प्रक्रिया की देखरेख का व्यापक अधिकार दिया है ताकि सत्ता परिवर्तन शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से हो सके। निर्वाचन आयोग स्वयं अपने संवैधानिक दायित्व को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने से जोड़ता है।लेकिन लोकतांत्रिक संस्थाओं की प्रतिष्ठा केवल संवैधानिक प्रावधानों से नहीं बनती। वह जनता के विश्वास से बनती है। इसलिए निर्वाचन आयोग के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज यही है कि उसकी प्रत्येक कार्रवाई ऐसी हो जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को समान रूप से भरोसा हो।

ट्रंप के बयान के बाद भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार को अमेरिका ले जाने संबंधी व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। यह प्रतिक्रिया बताती है कि भारत में निर्वाचन आयोग को लेकर राजनीतिक विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है।यदि सरकार निर्वाचन आयोग की प्रशंसा करे तो विपक्ष को संदेह हो सकता है। यदि विपक्ष आयोग पर सवाल उठाए तो सरकार इसे राजनीतिक हमला बता सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच संस्थागत निष्पक्षता का प्रश्न कहीं अधिक महत्वपूर्ण है।निर्वाचन आयोग को न तो सरकार के पक्ष में दिखाई देना चाहिए और न विपक्ष के। उसे केवल संविधान के पक्ष में दिखाई देना चाहिए।

यदि अमेरिका भारत से कुछ सीखना चाहता है तो केवल मतदाता पहचान-पत्र की व्यवस्था को देखकर बात पूरी नहीं हो सकती। भारत की चुनाव प्रणाली एक पूरे संस्थागत ढांचे पर आधारित है। मतदाता सूची, निर्वाचन क्षेत्र, मतदान केंद्रों का प्रबंधन, चुनावी आचार संहिता, राजनीतिक दलों के साथ संवाद, चुनाव अधिकारियों की तैनाती और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से लेकर मतगणना तक एक विस्तृत व्यवस्था काम करती है।

भारत में चुनाव आयोग को चुनावों के दौरान समान अवसर उपलब्ध कराने और आदर्श आचार संहिता लागू करने की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। संविधान का अनुच्छेद 324 इस पूरे ढांचे की आधारशिला है।

अमेरिका यदि भारतीय अनुभव से कुछ ग्रहण करता है तो उसे केवल पहचान-पत्र नहीं, बल्कि चुनाव प्रबंधन की संस्थागत संरचना पर भी विचार करना होगा। यहां बात केवल अमेरिका को भारत से सीखने की नहीं है। भारत को भी अपने चुनावी तंत्र में लगातार सुधार करते रहना होगा। आज मतदाता पहले से अधिक जागरूक है। सोशल मीडिया के दौर में चुनावी जानकारी कुछ सेकंड में करोड़ों लोगों तक पहुंच सकती है। गलत सूचना, डीपफेक, फर्जी वीडियो और डिजिटल प्रचार चुनावी वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं।ऐसे में निर्वाचन आयोग की पारदर्शिता और संवाद की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।मतदाता सूची में किसी नागरिक का नाम क्यों जोड़ा गया या क्यों हटाया गया, चुनावी निर्णय किस आधार पर लिया गया, राजनीतिक दलों की शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई-इन सभी सवालों के जवाब समय पर और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होना लोकतंत्र के हित में है।डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की ओर ध्यान जाना निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय हो सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की चुनावी व्यवस्था को अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा उदाहरण के तौर पर पेश करना भारत की संस्थागत क्षमता को अंतरराष्ट्रीय पहचान देता है।लेकिन लोकतंत्र में बाहरी प्रशंसा से ज्यादा महत्वपूर्ण आंतरिक विश्वास है।यदि भारत के नागरिक अपने निर्वाचन आयोग पर भरोसा करते हैं, यदि राजनीतिक दल चुनावी परिणामों को स्वीकार करते हैं और यदि हर मतदाता को यह विश्वास रहता है कि उसका वोट सुरक्षित है तथा उसकी आवाज सुनी जाएगी, तभी चुनाव प्रणाली वास्तव में मजबूत कही जाएगी।आज आवश्यकता इस बात की है कि निर्वाचन आयोग अपनी उपलब्धियों पर संतुष्ट होकर न रुके। उसे लगातार खुद को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होगा।ट्रंप को भारत इसलिए भाया क्योंकि उन्हें अपनी घरेलू राजनीतिक बहस के लिए भारतीय मॉडल में कुछ उपयोगी तत्व दिखाई दिए। लेकिन भारत के लिए इससे बड़ा संदेश यह है कि हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं दुनिया के लिए उदाहरण बन सकती हैं-बशर्ते हम उनके प्रति जनता का विश्वास बनाए रखें। चुनाव केवल सत्ता चुनने की प्रक्रिया नहीं है। चुनाव लोकतंत्र में नागरिक और राज्य के बीच विश्वास का सबसे बड़ा सेतु है। निर्वाचन आयोग उस सेतु का प्रहरी है।

इसलिए ट्रंप की प्रशंसा अच्छी खबर हो सकती है, लेकिन असली परीक्षा यह है कि भारत का आम मतदाता अपने निर्वाचन आयोग के बारे में क्या सोचता है। लोकतंत्र की अंतिम कसौटी वाशिंगटन की प्रशंसा नहीं, बल्कि भारत के मतदान केंद्र पर खड़ा वह सामान्य नागरिक है जो अपने हाथ में मतदाता पहचान-पत्र लेकर यह विश्वास करता है कि उसकी एक-एक वोट की कीमत है। और यही विश्वास भारत के निर्वाचन आयोग की सबसे बड़ी पूंजी है।

लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अ निवार्य नहीं है)

संपादकीय

एक खत्म, दूसरा शुरू

झारखंड में करीब 25 दिन तक चले छात्र आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विवादित कंपनी टीडीपीएल के संचालन में हुई जेपीएससी-14, जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की। साथ ही घोषणा कर दी कि जेपीएससी 11 व 13 की भी जांच की जाएगी। इसके अलावा परीक्षाओं के घोषित परिणाम भी रद्द करने का ऐलान कर दिया गया। यानी टीडीपीएल के माध्यम से जो भी अभ्यर्थी चुने गए, उनका चयन भी रद्द कर दिया गया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने सचिवालय में ग्यारह मंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श किया। छात्र आंदोलन के दबाव में काम कर रही राज्य सरकार की कैबिनेट बैठक करीब साढ़े चार घंटे तक चली। दरअसल, छात्रों के कई खेमे अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार जिन परीक्षाओं को रद्द किया गया,उनमें चौदहवीं जेपीएससी सिविल सेवा रेगुलर, जेपीएससी बैकलॉग 2023, जेपीएससी बैकलॉग 2025, फॉरेस्ट रेंज अफसर, सहायक वन संरक्षक और सिविल जूनियर आदि की नियुक्तियां शामिल हैं। दरअसल, इन परीक्षाओं का संचालन जेपीएससी के माध्यम से किया गया। वहीं दूसरी ओर सीजीएल परीक्षा से चयनित 1975 लोगों की नौकरियां भी अब समाप्त मानी जाएंगी। सरकार ने वायदा किया है कि वर्ष 2014 के बाद हुई सभी नियुक्ति परीक्षाओं की जांच भी की जाएगी। यह जांच कार्य एक न्यायिक आयोग करेगा। बाकायदा एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में सुधारों के लिये एक कमेटी भी बनायी गई है। हालांकि, कुछ आंदोलनकारी छात्र सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। हालांकि, सरकार की घोषणा के बाद छात्रों का आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन इस घोषणा के बाद सचिवालय परिसर में उन नियुक्त प्रतिभागियों की भीड़ जुट गई, जो जेएसएससी के माध्यम से परीक्षा उतीर्ण करके नौकरी हासिल कर चुके थे। सरकार की घोषणा के तुरंत बाद विभिन्न चयनित प्रतिभागियों का हुजूम सचिवालय में जमा होना शुरू हुआ। उनके लिये यह खबर स्तब्ध करने वाली थी। उनका दुख और गुस्सा स्वाभाविक ही है। बहरहाल, अब राज्य सरकार के खिलाफ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में चयनित होने के बाद हटाये गए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना था कि मुख्यमंत्री एक बयान देकर दो हजार लोगों को सरकारी नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं? वे इसे सरकारी अन्याय बता रहे हैं। उनकी दलील है कि हम सुबह नौकरी पर थे,लेकिन शाम होते ही हमें नौकरी से हटा दिया गया। उनका कहना था कि कोर्ट के आदेश के बाद ही हमें नौकरी मिली है। उल्लेखनीय है कि जेएसएससी-सीजीएल की परीक्षा दिसंबर 2023 में आयोजित हुई थी। लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा सितंबर 2024 में फिर से हुई। फिर पेपर लीक की आशंका के बीच मामला अदालत पहुंचा। कोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था। साथ ही तीस दिसंबर को सफल प्रत्याशियों को बाकायदा नौकरी के लिए नियुक्ति पत्र दे दिए गए। अब सरकार द्वारा ये नियुक्तियां रद्द करने से प्रतिभागी बदहवास हैं क्योंकि कई लोगों ने लोन लेकर अपना जीवन स्तर सुधारा, उनकी बैंक की किश्तें जा रही हैं। अब उनकी आंखों के सामने अंधेरा है। उनकी मांग है कि सरकार कायदे से जांच कर ले, लेकिन उन्हें नौकरी से न हटाए। सभी लोग धांधली से भर्ती नहीं हुए हैं। उनका तर्क है कि भीड़ के दबाव में निर्दोष लोगों को सजा नहीं दी जा सकती। हटाये गए कर्मचारियों की आंखें नम हैं। उनमें कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दूसरी नौकरियां छोड़कर सरकारी नौकरी के प्रलोभन में आए। दुखी व हताश हटाये गए कर्मचारी बारिश में धरने पर बैठे रहे क्योंकि उन्हें अधिकारियों ने सचिवालय से बाहर कर दिया था।

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की राह पर तेजी से आगे बढ़ता भारत

(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

- भारत के ऊर्जा भविष्य की नई तस्वीर

(अक्षय ऊर्जा दिवस (20 अगस्त) पर विशेष)

पृथ्वी पर ऊर्जा के परम्परागत साधन बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, ऐसे में खतरा मंडरा रहा है कि यदि ऊर्जा के इन पारम्परिक स्रोतों का इसी प्रकार दोहन किया जाता रहा तो इन परम्परागत स्रोतों के समाप्त होने पर गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही कारण है कि पूरी दुनिया में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने की जरूरत महसूस की जाने लगी और इसी कारण अक्षय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति करने के प्रयास शुरू हुए। अक्षय का अर्थ है, जिसका कभी क्षय न हो अर्थात् अक्षय ऊर्जा वास्तव में ऊर्जा का असीम और अनंत विकल्प है और आज के समय में यह किसी भी राष्ट्र के अक्षय विकास का प्रमुख स्तंभ भी है। पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरणीय चिंताओं को देखते हुए ऐसी ऊर्जा तथा तकनीकें विकसित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिनसे ग्लोबल वार्मिंग की विकराल होती समस्या से दुनिया को कुछ राहत मिल सके। किसी भी राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए आज प्रदूषणरहित अक्षय ऊर्जा स्रोतों का समुचित उपयोग किए जाने की आवश्यकता भी है। देश में अक्षय ऊर्जा के विकास और उपयोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए ही वर्ष 2004 से हर साल 20 अगस्त को 'अक्षय ऊर्जा दिवस' भी मनाया जाता है। आज न केवल भारत में बल्कि समूची दुनिया के समक्ष बिजली जैसी ऊर्जा की महत्वपूर्ण जरूरतों को पूरा करने के लिए सीमित प्राकृतिक संसाधन हैं, साथ ही पर्यावरण असंतुलन और विस्थापन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हैं। चर्चित पुस्तक 'प्रदूषण मुक्त सांसें' के अनुसार इन गंभीर समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए अक्षय ऊर्जा ही एक ऐसा बेहतरीन विकल्प है, जो पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के साथ-साथ ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करने में भी कारगर साबित होगी लेकिन अक्षय ऊर्जा की राह में भी कई चुनौतियां मुंह बाये सामने खड़ी हैं। अक्षय ऊर्जा उत्पादन की देशभर में कई छोटी-छोटी इकाईयां हैं, जिन्हें एक ग्रिड में लाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। इससे बिजली की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भारत में अक्षय ऊर्जा के विविध स्रोतों का अपार भंडार मौजूद है लेकिन इनसे ऊर्जा उत्पादन करने वाले अधिकांश उपकरण विदेशों से आयात किए जाते हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, कुछ साल पहले सौर ऊर्जा के लिए करीब 90 प्रतिशत उपकरण विदेशों से आयात किए गए थे, जिससे बिजली उत्पादन की लागत काफी बढ़ गई। अब भी भारत की सौर सेल और मॉड्यूल की जरूरत का अधिकांश हिस्सा आयात से ही पूरा हो रहा है। हालांकि हाल के वर्षों में एएलएमएम नियम और पीएलआई स्कीम के कारण यह निर्भरता घट रही है। 2023-24 में चीन से सौर सेल्स का 53 प्रतिशत और मॉड्यूल्स का 63 प्रतिशत भारत में आया। देश में ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भी तेजी से बढ़ रहा है। देश में कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में अब बड़ा हिस्सा अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रहा है, जिसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो-पावर और छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अधिक बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं से तथा परमाणु ऊर्जा से भी अक्षय ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है। कुल बिजली उत्पादन में अब अक्षय ऊर्जा का हिस्सा अब लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को दुनिया के अग्रणी देशों में शामिल करता है। भारत में ऊर्जा खपत भी तेजी से बढ़ रही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) का अनुमान है कि वर्ष 2040 तक भारत में ऊर्जा की कुल मांग वर्तमान की तुलना में लगभग दोगुनी हो जाएगी। विशेषकर बिजली तथा ईंधन के रूप में उपभोग की जा रही ऊर्जा की मांग घरेलू एवं कृषि क्षेत्र के अलावा औद्योगिक क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक क्षेत्रों में ही बिजली तथा पैट्रोलियम जैसे ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोतों का लगभग 55 प्रतिशत उपभोग किया जाता है। हम जिस बिजली से अपने घरों, दुकानों या दफ्तरों को रोशन करते हैं, जिस बिजली या पैट्रोलियम इत्यादि ऊर्जा के अन्य स्रोतों का इस्तेमाल कर खेती-बाड़ी या उद्योग-धंधों के जरिये देश को विकास के पथ पर अग्रसर किया जाता है, क्या हमने कभी सोचा है कि वह बिजली या ऊर्जा के अन्य स्रोत हमें कितनी बड़ी कीमत पर हासिल होते हैं? यह कीमत न केवल आर्थिक रूप से बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी धरती पर विद्यमान हर प्राणी पर बहुत भारी पड़ती है। भारत में थर्मल पावर स्टेशनों में बिजली पैदा करने के लिए प्रतिदिन लगभग 18 लाख टन कोयले की खपत होती है। आज भी देश की लगभग 70 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले से ही पैदा होती है, शेष बिजली अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जल, गैस व परमाणु ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है। दुनियाभर में ऊर्जा क्षेत्र में लगभग 75 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन बिजली उत्पादन से ही होता है। यही कारण है कि अब सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसे अक्षय ऊर्जा स्रोतों को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, यदि अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता पर विशेष ध्यान दिया जाए तो वर्ष 2050 तक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को 70 प्रतिशत तक घटाया जा सकता है। भारत ने भी 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता हासिल करने और नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य वर्ष 2070 तक प्राप्त करने का संकल्प लिया है। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग को बढ़ावा देने से हमारी ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर कम होता जाएगा और इससे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन स्तर में भी सुधार होगा।

भारत में अब ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्मार्ट ग्रिड, बैटरी स्टोरेज और इलैक्ट्रिक मोबिलिटी जैसे कदम भी तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं, जो अक्षय ऊर्जा को व्यावहारिक और टिकाऊ बनाएंगे। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 तक 5 मिलियन मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिससे भारत न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि निर्यातक देश भी बन सकेगा। सही मायने में अक्षय ऊर्जा ही आज भारत में विभिन्न रूपों में ऊर्जा की जरूरतों का प्रमुख विकल्प है, जो पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ टिकाऊ भी है। भारत धीरे-धीरे ही सही, अब इस दिशा में आगे बढ़ रहा है और आज समय है कि हम आर्थिक बदहाली और भारी पर्यावरणीय विनाश की कीमत पर ताप, जल एवं परमाणु ऊर्जा जैसे पारम्परिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भर रहने के बजाय अपेक्षाकृत बेहद सस्ते और कार्बन रहित पर्यावरण हितैषी ऊर्जा स्रोतों के व्यापक स्तर पर विकास के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ें।

प्राणवान प्रतिभाओं की खोज

प्रगति पथ पर अग्रसर होने के लिए तदनुरूप योग्यता एवं कर्मनिष्ठा उत्पन्न करनी पड़ती है। साधन जुटाने पड़ते हैं। कठिनाइयों से जूझने, अड़चनों को निरस्त करने और मार्ग रोककर बैठे हुए अवरोधों को हटाने के लिए साहस, शौर्य और सूझबूझ का परिचय देना पड़ता है। जो कठिनाइयों से जूझ सकता है और प्रगति की दिशा में बढ़ चलने के साधन जुटा सकता है, उसी को प्रतिभावान कहते हैं। सामुदायिक सार्वजनिक क्षेत्र में सुव्यवस्था बनाने के लिए और भी अधिक प्रखरता चाहिए। यह विशाल क्षेत्र, आवश्यकताओं और गुत्थियों की दृष्टि से तो और भी बढ़ा-चढ़ा होता है। हीन वर्ग अपने साधनों के लिए, मार्गदर्शन के लिए दूसरों पर निर्भर रहता है। यह परजीवी वर्ग ही मनुष्यों में बहुलता के साथ पाया जाता है। अनुकरण और आश्रय ही उसका स्वभाव होता है। ऐसे लोग निजी निर्धारण कदाचित ही कभी कर पाते हैं। दूसरा वर्ग-समझदार होते हुए भी संकीर्ण स्वार्थपरता से घिरा रहता है। योग्यता और तत्परता जैसी विशेषताएं होते हुए भी ऐसे लोग अपने को लोभ, अहंकार की पूर्ति के लिए ही नियोजित किए रहते हैं।

वे कृपणता और कायरता के दबाव में वे पुण्य-परमार्थ की बात सोच ही नहीं पाते। अवसर मिलने पर अनुचित कर बैठते हैं और महत्व न मिलने पर अनर्थ कर बैठते हैं। वे जैसे-तैसे जी लेते हैं, पर श्रेय सम्मान जैसी किसी मानवोचित्त उपलब्धि के साथ उनका संबंध नहीं जुड़ता। उन्हें जनसंख्या का घटक भर माना जाता है। तीसरा वर्ग प्रतिभाशालियों का है। ये भौतिक क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए अनेक व्यवस्थाएं बनाते हैं। ये अनुशासन और अनुबंधों से बंधे रहते हैं। अपनी नाव अपने बलबूते खेते हैं और उसमें बिठाकर अन्यों को भी पार करते हैं। कारखानों के व्यवस्थापक और शासनाध्यक्ष प्राय- इन्हीं विशेषताओं से सम्पन्न होते हैं। बोलचाल की भाषा में उन्हें ही प्रतिभावान कहते हैं।सबसे ऊंची श्रेणी देवमानवों की है, जिन्हें महापुरुष भी कहते हैं। प्रतिभा तो उनमें भरपूर होती हैं, पर वे उसका उपयोग आत्म परिष्कार से लेकर लोकमंगल तक उच्च स्तरीय प्रयोजनों में लगाते हैं। निजी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं के बजाय अपने शक्ति भंडार को परमार्थ में लगाते हैं। किसी देश की सच्ची संपदा वे ही समझे जाते हैं। वे अपने कार्य क्षेत्र को नंदनवन जैसा सुवासित करते हैं। जहां भी बादलों की तरह बरसते हैं, वहीं मखमली हरीतिमा का फर्श बिछा देते हैं और वसंत की तरह अवतरित होते हैं।

विचार मंथन

सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच का आक्रामक रुख

(लेखक- सनत जैन)

नीट यूजी पेपर लीक मामले में जंतर मंतर में 20 जुलाई को आंदोलन के दौरान संसद मार्च का आवाहन किया गया था। इस मार्च में पुलिस ने छात्रों के ऊपर अश्रु गैस, वॉटर कैनन, लाठी चार्ज, पैलट गन से छात्रों पर गोलीबारी, बिना वर्दी के पुलिसकर्मी, कुछ असामाजिक तत्वों एवं पुलिस द्वारा की गई बर्बरता के खिलाफ यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने हलफनामा दायर किया है, जिसमें कहा गया है, छात्रों का यह मार्च गैर कानूनी था। इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। कई हिस्ट्रीशीटर भी इस आंदोलन में शामिल थे। प्रदर्शनकारियों पर सामान्य बल का प्रयोग किया गया है। हलफनामे में बताया गया है, 30000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी मौजूद थे। उन्हें नियंत्रित करने के लिए बल प्रयोग किया गया। हलफनामे के अनुसार 240 पुलिसकर्मी और 200 प्रदर्शनकारी घायल हुए थे। दिल्ली पुलिस ने कहा, इस तरह के आंदोलन में सादे कपड़ों में पुलिस को तैनात किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक हाईपावर कमेटी बनाकर जांच करने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट के इस प्रस्ताव पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा हम जांच नहीं न्याय चाहते हैं।

यदि सुप्रीम कोर्ट चाहती है, कोई कमेटी बनाकर जांच कराई जाए, तो निष्पक्ष जाँच के लिये पूर्व जज, सीबीआई अधिकारी, डीजीपी इत्यादि जो भी सुप्रीम कोर्ट रखना चाहती है। उसके लिए उनका निष्पक्ष होना जरूरी है। कमेटी गठित करने के पहले याचिकाकर्ताओं की सहमति ली जानी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने कहा, हम ऐसी किसी कमेटी को स्वीकार नहीं करेंगे, जिसमें वह लोग शामिल हों, जिनकी निष्ठा हमेशा सरकार के प्रति रही है। वह सरकार के इशारे पर काम करते हैं। सौरभ दास ने यहां तक कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने सभी सबूत मय वीडियो प्रस्तुत किए हैं। उसके आधार पर फैसला होना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट यदि चाहता है, जाँच के लिए कमेटी बनाई जाए, तो इस कमेटी में कॉकरोच पार्टी के लोगों को भी शामिल किया जाए। कमेटी किस तरह से काम कर रही है, याचिकाकर्ता भी कमेटी के सामने अपने पक्ष और सबूत रख सकें। निश्चित समय पर इसकी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हो। पहले भी जिस तरह की जांच कमेटी बनती रही हैं, उसमें सरकार के प्रति निष्ठावान सदस्य होते हैं। लंबे समय तक जाँच टलती है। इस तरह की कमेटी से हमें कोई न्याय की आशा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाने के पहले उसके सदस्यों की निष्पक्षता एवं विश्वसनीयता पर ध्यान देना होगा। तभी हम कमेटी को स्वीकार करेंगे। यह पहली बार हुआ है, जब सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच के लिए जो कमेटी बनाई जा रही है।

उसके सदस्यों को लेकर इस तरह की बात सुप्रीम कोर्ट में, इसके पहले कभी देखने को नहीं मिली। न्यायपालिका को लेकर जिस तरह का अविश्वास सारे देश में देखने को मिल रहा है, यह चिंता में डालने वाला है। न्यायपालिका को सुनिश्चित करना होगा, जो कमेटी बनाई जा रही है। उसमें जो भी सदस्य नियुक्त किए जाएं उनकी निष्पक्षता पर यदि अविश्वास होगा, सरकार की ओर से नामित व्यक्तियों को सदस्य बनाया जाएगा। वह सरकार और पुलिस को बचाने के लिए काम करेंगे। ऐसी किसी कमेटी को याचिकाकर्ता स्वीकार नहीं करेंगे।

कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास ने जो बात सार्वजनिक मंच पर जाकर कही है, उससे स्पष्ट है, कॉकरोच जनता पार्टी के तेवर काफी आक्रामक है। कॉकरोच जनता पार्टी, जांच कमेटी के जाल में फंसना नहीं चाहती है। वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सबूतों के आधार पर मामले की सुनवाई कर जल्द से जल्द फैसला देने की मांग पर अड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के सामने सबसे बड़ी दुविधा, वह दोनों पक्षों को किस तरह से मामले की सुनवाई, जांच कमेटी के सदस्यों पर सहमति बनाने की है, वर्तमान में जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, उसमें न्यायपालिका पर विश्वास का संकट है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की खंडपीठ में इस मामले की सुनवाई चल रही है। उन्होंने ही कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट में पुलिस बर्बरता के वीडियो के साथ मामले की सुनवाई का आग्रह किया गया था। उस समय मुख्य न्यायाधीश द्वारा यह कहा गया था, अभी हमारे पास समय नहीं है, आप भी अपना समय बर्बाद ना करें। उसके बाद से न्यायपालिका भी जेन-जेड और कॉकरोच जनता पार्टी के निशाने पर है। पहली बार न्यायपालिका को लेकर मुखरता के साथ अविश्वास देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कई राज्यों के छात्र सड़कों पर हैं। जेन-अल्फा भी सड़कों पर है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को संवेदनशीलता के साथ इस विवाद को सुलझाना होगा।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सोने-चांदी में नरमी

मुम्बई ।

घरेलू बाजार में बुधवार को सोने और चांदी में तेज गिरावट रही। ये गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव और निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली के चलते आई है। सुबह सोने के वायदा भाव में 362 रुपये जबकि चांदी में 2,418 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी आई। इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण 30 साल के अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड का 19 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना रहा। हालांकि, फेडरल रिजर्व द्वारा निकट भविष्य में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम होने के कारण सोना और चांदी के लिए एक सकारात्मक कारक बना हुआ है, जो भविष्य में कीमतों को सहारा दे सकता है।वहीं अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर, सोना 4,410 डॉलर प्रति औंस के करीब कारोबार कर रहा था जबकि चांदी 63 प्रति औंस के करीब थी। वहीं मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, सोने के वायदा भाव 1,54,200 रुपये के स्तर पर थे जबकि चांदी के भाव करीब 2,30,250 के आसपास थे। एमसीएक्स पर सोने के अक्टूबर अनुबंध की शुरुआत 362 रुपये की गिरावट के साथ 1,53,900 पर हुई। इसका पिछला बंद भाव 1,54,262 रुपये था। दिन के कारोबार के दौरान, यह अनुबुंध 69 रुपये की गिरावट के साथ 1,54,193 रुपये पर कारोबार कर रहा था, जिसने दिन में कीमतें 1,53,900 रुपये के निचला स्तर और 1,54,326 के उच्च स्तर पर पहुंची। इस साल सोना 1,80,779 रुपये के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचा था। वहीं चांदी के सितंबर अनुबंध की भी कमजोर शुरुआत रही उसमें 2,418 रुपये की बड़ी गिरावट देखी गई और यह 2,30,001 पर खुली। इसका पिछला बंद भाव 2,32,419 रुपये था। कारोबार के समय यह अनुबंध् 2,181 की गिरावट के साथ ही 2,30,238 रुपये पर था, जिसने दिन के दौरान 2,29,666 रुपये का निचला और 2,30,528 रुपये का उच्च स्तर हासिल किया। चांदी इस साल 4,20,048 प्रति किलो के उच्चतम स्तर पर पहुंची। दूसरी ओर अंतरराष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स पर सोने के वायदा भाव 4,391.40 डॉलर प्रति औंस पर खुले, जो अपने पिछले बंद भाव 4,420.60 से कम थे। कारोबार के दौरान यह 11.20 रुपये की गिरावट के साथ 4,409.40 प्रति औंस पर थे। इस साल सोने ने 5,586.20 डॉलर का रिकॉर्ड उच्च स्तर देखा। इसी तरह, कॉमैक्स पर चांदी के वायदा भाव 63.42 डॉलर पर खुले, जो पिछले बंद भाव 64.03 डॉलर से नीचे था।

बेहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह

लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर को लेकर मिल रहे मजबूत संकेत

नई दिल्ली,। बेहारी लाल इंजीनियरिंग के शेयर बुधवार को बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध होने जा रहे हैं। कंपनी के शुरुआती सार्वजनिक निर्गम यानी आईपीओ को लेकर निवेशकों में काफी उत्साह है। 17 अगस्त को शेयर आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब सभी की नजर लिस्टिंग पर है। लिस्टिंग से पहले ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर को लेकर मजबूत संकेत मिल रहे हैं। बुधवार सुबह शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम करीब 133 रुपए चल रहा था। कंपनी ने आईपीओ में शेयर का ऊपरी मूल्य बैंड 285 रुपए तय किया था। इस हिसाब से संभावित लिस्टिंग कीमत करीब 418 रुपए होती है यानी इश्यू मूल्य के मुकाबले करीब 46.67 फीसदी प्रीमियम पर शेयर सूचीबद्ध होने का अनुमान लगाया जा रहा था। हालांकि ग्रे मार्केट प्रीमियम अनौपचारिक संकेत होता है और वास्तविक लिस्टिंग कीमत इससे अलग हो सकती है।बेहारी लाल इंजीनियरिंग का आईपीओ 301.62 करोड़ रुपए था। इसमें 93 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए गए, जबकि 208.62 करोड़ रुपए का हिस्सा ऑफर फॉर सेल के जरिए था। आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 271 से 285 रुपए प्रति शेयर रखा गया था। निवेशकों को न्यूनतम 52 शेयरों के लिए आवेदन करना था। ऊपरी मूल्य बैंड के आधार पर खुदरा निवेशकों का न्यूनतम निवेश 14,820 रुपए था। बता दें कंपनी की स्थापना 1995 में हुई थी। यह लौह और इस्पात से जुड़े उत्पादों के अलावा विभिन्न उद्योगों के लिए इंजीनियरिंग उत्पाद बनाती है। इसके उत्पादों में मेटल रोल्स, इंजीनियरिंग कास्टिंग, मिश्र धातु इस्पात उत्पाद, फोर्जिंग इंगोट्स और फोर्ज्ड शाफ्ट शामिल हैं।31 मार्च 2026 तक कंपनी के ग्राहक आधार में भारत और विदेशों के 1,825 ग्राहक शामिल थे। इसकी विनिर्माण इकाइयां पंजाब के मंडी गोबिंदगढ़ में हैं। 31 मई 2026 तक कंपनी के पास करीब 178.57 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक था। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग के दौरान ग्रे मार्केट में दिख रहा उत्साह कितना बरकरार रहता है।

शेयर बाजार गिरावट पर बंद

सेंसेक्स 325, निफ्टी 76 अंक गिरा

मुंबई ।

भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को भी गिरावट रही। वहीं गत दिवस भी ये गिरा था। बाजार में ये गिरावट दुनिया भर से मिले कमजोर संकेतों के साथ ही बिकवाली हावी रहने से आई है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव के कारण कच्चे तेज की कीमतें बढ़ने से भी घरेलू बाजार पर दबाव पड़ा है। बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी से भी बाजार धारणा प्रभावित हुई।

आज कारोबार के दौरान पावर ग्रिड, बजाज फाइनेंस, एलएंडटी, आईटीसी के शेयर गिरे हालांकि, कुछ आईटी शेयरों ने बाजार की इस गिरावट को थामा।

दिन भर के कारोबार के बाद 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 325.78 अंक की गिरावट के साथ ही 76,909.68 अंकों पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 76.60 अंकों की गिरावट के साथ ही 24,078.30 अंकों पर बंद हुआ।

बाजार की व्यापक स्थिति कमजोर रही। सेंसेक्स में सूचीबद्ध 30 कंपनियों में से केवल 8 के शेयर ही लाभ के साथ बंद हुए। वहीं 21 अन्य में गिरावट रही। इसी तरह, निफ्टी की 50 कंपनियों में से 34 के शेयर नीये आये जबकि केवल 16 में तेजी दर्ज की गई।

सरकारी बिजली कंपनी पावर ग्रिड के शेयरों में सबसे ज्यादा 2.00 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई, जो सेंसेक्स के लिए सबसे बड़ा झटका था। इसके विपरीत, आईटी क्षेत्र से एचसीएल टेक का शेयर 1.73 फीसदी की बढ़त के साथ शीर्ष पर रहा

गिरावट दर्ज करने वाले प्रमुख शेयरों में बजाज फाइनेंस , एलएंडटी , आईटीसी , हिंदुस्तान यूनिलीवर आदि रहे जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, सन फार्मा , टाइटन , टीसीएस , इन्फोसिस और ट्रेंट के शेयरों में तेजी रही। बजाज फिनसर्व के शेयर बिना किसी बदलाव के सपाट रहे।

इससे पहले आज सुबह

सेंसेक्स करीब 94.57 अंक की गिरावट के साथ 77,140.89 के स्तर पर कारोबार कर रहा था जबकि 50 शेयरों वाल एनएसई निफ्टी50 भी 38.30 अंक फिसलकर 24,116.60 पर पहुंच गया।वैश्विक बाजारों में भी कमजोरी का सिलसिला जारी रहा। अमेरिकी शेयर बाजारों में मंगलवार को नैस्डैक कंपोजिट 1.33 फीसदी और एसएंडपी 500 0.69 फीसदी की गिरावट के साथ लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में गिरे। डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी लगभग 0.2 फीसदी नीचे बंद हुआ।दूसरी ओर एशियाई बाजारों में भी बिकवाली का दबाव बढ़ा हुआ था। दक्षिण कोरिया का कोस्पी इंडेक्स लगभग 4.2 फीसदी तक गिर गया।

बाल यौन शोषण सामग्री कानून का उल्लंघन, मेटा से बातचीत के बाद सरकार सख्त

नई दिल्ली।

अमेरिकी कंपनी मेटा के साथ सरकार की बातचीत के बाद बाल यौन शोषण सामग्री के मुद्दे पर कार्रवाई में तेजी आई है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि केंद्र ने साफ कर दिया है कि ऐसी सामग्री कानून का स्पष्ट उल्लंघन है और इस तरह का उल्लंघन होने पर 'सेफ हार्बर' का संरक्षण नहीं मिलेगा। 'सेफ हार्बर' एक कानूनी प्रावधान है जो इंटरनेट मध्यस्थों और सोशल मीडिया मंचों को उपयोगकर्ताओं द्वारा 'पोस्ट' की गई सामग्री के लिए कानूनी जिम्मेदारी या मुकदमों से बचाता है।सूत्रों ने बताया कि सरकार का मकसद 'सेंसरशिप' या किसी भी तरह से 'कवरेज' को सीमित करना नहीं है, बल्कि भारतीय कानूनों और नियमों का पालन तय करना और सोशल मीडिया से होने वाले नुकसान को कम करना है। उन्होंने कहा कि संदेश पहुंच गया है। आईटी मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि मेटा ने सीएसएएम पर बढ़ी हुई संवेदनशीलता और सावधानी दिखाई है और हालिया चर्चाओं के बाद सरकार को कंपनी द्वारा कुछ कार्रवाई होती दिख रही है। सूत्रों ने इस प्रतिक्रिया को 'महत्त्वपूर्ण और उल्लेखनीय' बताया। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि बातचीत में मेटा ने बताया कि उसके 'एल्गोरिदम' और प्रणालियां कैसे काम करती हैं।

कच्चे तेल की कीमतों में आई तेजी

मुम्बई ।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड (कच्चे तेल) की बढ़ती कीमतों में तेजी आई है। ऐसे में अभी पेट्रोल-डीजल के दाम कम होने की जगह बढ़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ किसी भ्री तरह से बातचीत करने से इंकार करने के बाद से ही करने के बयान के बाद से ही कच्चे तेल की कीमतें 91 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गई हैं। आज सुबह कच्चा तेल 38 सेंट चढ़कर 91.40 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया जबकि डब्लयूटीआई क्रूड 45 सेंट की बढ़त के साथ ही 85.30 डॉलर प्रति बैरल पर था। कच्चे तेल की कीमतों में आये इस उछाल से ईंधन की कीमतें बढ़ना तय है।

एक अनुमान के मुताबिक, एक बैरल कच्चे तेल की कीमत में 10 डॉलर की बढ़ोतरी से कंपनियों को प्रति लीटर लगभग 6 रुपये का नुकसान होता है।

वहीं देश में आज पेट्रोल-डीजल के रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपये और डीजल 95.20 रुपये प्रति लीटर पर स्थिर बना हुआ है। इसके साथ ही, एलपीजी और सीएनजी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं हुआ।

एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना बंद- बॉन्ड बाजार पर दबाव, यील्ड में वृद्धि

नई दिल्ली, ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना के समय से पहले बंद होने से बॉन्ड बाजार पर, विशेषकर अल्पावधि बॉन्ड खंड पर दबाव बढ़ा है। इसके परिणामस्वरूप, पांच वर्षीय बॉन्ड की यील्ड 6.44 प्रतिशत से बढ़कर 6.46 प्रतिशत पर पहुंच गई है।

बीते दो कारोबारी सत्रों में पांच वर्षीय बॉन्ड की यील्ड में करीब 10 आधार अंक की वृद्धि दर्ज की गई। 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड की यील्ड भी 6.81 प्रतिशत से बढ़कर 6.83 प्रतिशत पर बंद हुई। डीलरों का अनुमान है कि अगस्त के अंत तक यह 6.85 प्रतिशत के करीब पहुंच सकती है। गौरतलब है कि आरबीआई की योजना ने पहले अल्पावधि बॉन्ड को बेहतर प्रदर्शन करने में मदद की थी।

बाजार के जानकारों के अनुसार, कारोबारियों ने एफसीएनआर (बी) के तहत 3 से 5 साल की अवधि के लिए आने वाली जमा की उम्मीद में पांच वर्षीय बॉन्ड में बड़ी पोजीशन बनाई थीं। योजना के अचानक बंद होने से इन पोजीशन को समाप्त किया जा रहा है, जिससे कम अवधि वाले बॉन्ड खंड पर

अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। प्राइमरी डीलरशिप के वरिष्ठ अधिकारी ने पुष्टि की, कारोबारियों ने 5 वर्षीय बॉन्ड में ज्यादा पोजीशन बनाई थीं और अब उन्हें खत्म किया जा रहा है। एफसीएनआर (बी) स्वैप योजना के समाप्त होने के साथ ही, बाजार का ध्यान अब फिर से वैश्विक कारकों, विशेष तौर पर अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड और कच्चे तेल की कीमतों पर केंद्रित हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि एफसीएनआर (बी) सुविधा बॉन्ड बाजार के लिए एक सकारात्मक कारक थी और इसने बाजार को स्थिरता बनाए रखने में मदद की थी।

भारत में डीपटेक फंडिंग का बोलबाला, 11.4 अरब डॉलर का आंकड़ा पार

पिछले छह सालों में आया 85 फीसदी से ज्यादा निवेश

नई दिल्ली।

इंडियन वेंचर ऐंड ऑल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) की रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय डीपटेक सेक्टर में वर्ष 2015 से अब तक कुल 11.4 अरब डॉलर का भारी निवेश आया है। इस फंडिंग का 85 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा पिछले छह सालों में ही जुटाया गया है, जो देश के डीपटेक इकोसिस्टम के तेजी से परिपक्व होने और वाणिज्यिक सफलता की ओर बढ़ने का स्पष्ट संकेत देता है। आईवीसीए के आंकड़ों के मुताबिक डीपटेक सेक्टर में निवेश में अभूतपूर्व उछाल आया है। वर्ष 2025 फंडिंग के लिहाज से अब तक का सबसे सफल साल रहा, जब डीपटेक स्टार्टअप्स ने रिकॉर्ड 189 राउंड में 2.9 अरब डॉलर जुटाए। वर्ष 2026 में भी यह गति जारी है और कंपनियों ने 103 राउंड में लगभग 1 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है।

2021 के बाद से फंडिंग में आई यह तेजी साफ तौर पर दर्शाती है कि डीपटेक कंपनियां अब शुरुआती चरण से निकलकर वाणिज्यिक मजबूती की ओर अग्रसर हैं।

इस तेजी का प्रमाण हाल के उदाहरणों में देखा जा सकता है, जैसे स्काईरूट एरोस्पेस द्वारा पहले प्राइवेट ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट का सफल लॉन्च और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी नेसा का 1.2 अरब डॉलर का फंडिंग राउंड, जिसने उसे यूनिकॉर्न का दर्जा दिलाया। 2015 से 2026 के बीच ब्लूम वेंचर्स (51 सौदे), स्पेशल इन्वेस्ट (50 सौदे) और एक्सेल इंडिया (48 सौदे) सबसे सक्रिय डीपटेक निवेशक रहे। इसी अवधि में, डीपटेक कंपनियों ने 61 सौदों के माध्यम से वेंचर ऋण के रूप में कुल 54.4 करोड़ डॉलर की पूंजी भी जुटाई। हालांकि, निवेश से बाहर निकलने (एक्जिट) के लिए विलय एवं अधिग्रहण को प्राथमिकता दी जाती है, लेकिन हकीकत में सबसे ज्यादा सेकंडरी बिक्री (56 फीसदी) ही देखने को मिली हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 62 प्रतिशत फंडों ने एक्जिट की स्पष्टता को एक बड़ी चुनौती माना है।

आईपीओ भी एक विकल्प है, लेकिन इसके लिए ग्रोथ-स्टेज कैपिटल की अधिक आवश्यकता होती है।

पिछले साल 18 बिकवाली सौदों से 60 करोड़ डॉलर मिले, जबकि 2024 में 7 एक्जिट से 15.2 करोड़ डॉलर जुटाए गए। डीपटेक स्टार्टअप वे उद्यम हैं जो नई वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग प्रगति पर आधारित समाधान विकसित करते हैं, जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस-टेक, रक्षा और एयरोस्पेस, रोबोटिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग टेक्नॉलजी और अन्य उन्नत क्षेत्रों की कंपनियां शामिल हैं।

भारत का डीपटेक सेक्टर भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

रुपया बढ़त पर बंद

मुंबई ।

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले बुधवार को भारतीय रुपया 18 पैसे की बढ़त के साथ ही 95.57 पर बंद हुआ। वही गत दिवस रुपया 95.74 पर बंद हुआ। आज सबह रुपया 95.72 पर खुला। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में गत दिवस रुपया 95.68 प्रति डॉलर पर खुला रुपया सोमवार को 19 पैसे टूटकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95.61 पर बंद हुआ था। इस बीच दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की स्थिति को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक 0.01 फीसद टूटकर 99.63 पर रहा। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि ब्रेंट कच्चा तेल की कीमत के करीब 91 डॉलर प्रति बैरल पहुंचने से तेल से संबंधित डॉलर की मांग में वृद्धि हुई है।

ओपनएआई ने किशोरों के लिए शुरु किया नया चैटजीपीटी, सुरक्षा व्यवस्था होगी मजबूत

अभिभावक अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की कर सकेंगे निगरानी

नई दिल्ली,।

ओपनएआई ने 13 से 17 साल की उम्र के किशोर उपयोगकर्ताओं के लिए चैटजीपीटी सेवा शुरू की। कंपनी के मुताबिक इसमें ज्यादा मजबूत सुरक्षा व्यवस्था और अभिभावकों के नियंत्रण की सुविधा होगी यानी वे अपने बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों की निगरानी कर सकेंगे। यदि चैटजीपीटी के सिस्टम को शक होता है कि उपयोगकर्ता की उम्र 18 साल से कम है, तो यह नया फीचर अपने आप सक्रिय हो जाएगा। कंपनी ने कहा कि ऐसे उपयोगकर्ताओं को स्वचालित रूप से किशोरों के लिए चैटजीपीटी अनुभव में रखा जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा तय की जा सके।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओपनएआई ने कहा कि किशोरों के लिए चैटजीपीटी फीचर सीखने और सुरक्षा सुविधाओं को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य कक्षा के बाहर सक्रिय और सहयोगात्मक सीखने में मदद करना और एआई के ज्यादा सोच-समझ कर और उम्र के अनुरूप उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में ऐसी सामग्री से सुरक्षा शामिल है, जिसमें खुद को नुकसान पहुंचाने, हिंसा, खतरनाक गतिविधियों या किसी भी तरह की यौन रूप से स्पष्ट सामग्री का चित्रण हो। ओपनएआई

इंडिया में स्ट्रैटजी और वैश्विक मामलों की प्रमुख ने यह जानकारी दी।

डिजिटल भुगतान की बढ़त के बीच नगदी के प्रचलन में नहीं आई गिरावट

आरबीआई ने छह मूल्य वर्गों में सालाना 28 से 30 अरब बैंक नोटों की छपाई की

नई दिल्ली,।

डिजिटल भुगतान के बढ़ते इस्तेमाल के बीच व्यक्तिगत लेन-देन में नकदी की हिस्सेदारी भले ही कम हो रही है, लेकिन प्रचलन में नकदी की मात्रा दो अंकों की दर से लगातार बढ़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा कि इससे न केवल भविष्य के लिए नकदी की मांग का अनुमान लगाना कठिन हो गया है बल्कि बैंक नोटों के उत्पादन एवं वितरण क्षमता के लिए आरबीआई की योजना भी जटिल होती जा रही है।

मुर्मू ने कहा कि पिछले दशक में भारत में डिजिटल भुगतान को अपनाना क्रांतिकारी रहा है, लेकिन प्रचलन में नकदी की मात्रा में कोई गिरावट नहीं आई है। ऐसा खास तौर पर ग्रामीण एवं कस्बाई इलाकों में, कम आय वाले लोगों, बुजुर्गों और छोटे कारोबारियों के बीच देखा जा रहा है। मुर्मू ने बताया कि पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने छह मूल्य वर्गों में सालाना 28 से 30 अरब बैंक नोटों की छपाई की है और सालाना करीब 21 अरब बैंक नोटों का निपटान किया है। फिलहाल देश में 176 अरब बैंक नोट प्रचलन में हैं। इसके मुकाबले पिछले साल के आखिर में करीब 56 अरब डॉलर बिल और 30 अरब यूरो के बैंक नोट प्रचलन में थे।

उन्होंने कहा कि भारत में यह संख्या कुछ हद तक कम मूल्य वाले नोटों के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से है। इसका मतलब साफ है कि समान मूल्य के लेनदेन के लिए ज्यादा नोटों का आदान-प्रदान किया जाता है। भारत सरकार ने फील्ड ट्रायल के लिए 10 रुपए और 20 रुपए के 1 अरब पॉलिमर बैंक नोट लाने को मंजूरी दे दी है। अगर फील्ड ट्रायल और परिचालन संबंधी आकलन के नतीजे संतोषजनक रहे तो आरबीआई वित्त वर्ष 2028 की शुरुआत से परीक्षण के आधार पर पॉलिमर बैंक नोटों को प्रचलन में लाने की योजना बना रहा है। केंद्रीय बैंक ने पॉलिमर सबस्ट्रेट की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है लेकिन आरबीआई बड़े पैमाने पर जारी करने का फैसला लेने से पहले भारतीय जलवायु और उपयोग की परिस्थितियों में इन नोटों का परीक्षण करेगा। आरबीआई अपने वितरण नेटवर्क को अनुकूलित करके और बैंक नोट ब्रिगेट के निपटान के तरीके में सुधार के जरिये नकदी चक्र में कार्बन की मौजूदगी को कम करने के लिए भी काम कर रहा है।

मुर्मू ने कहा कि डिजिटल भुगतान में तेजी के बावजूद नकदी प्रबंधन केंद्रीय बैंकों के लिए एक प्रमुख जिम्मेदारी बनी हुई है।

इससे भौतिक मुद्रा में जनता के विश्वास को बनाए रखने के महत्त्व का पता चलता है।

दुबई का कमर्शियल रियल एस्टेट बाजार 8.5 फीसदी बढ़कर 65.23 अरब दिरहम हुआ

यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऑफिस सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन की वजह से हुई

नई दिल्ली,।

दुबई के वाणिज्यिक रियल एस्टेट बाजार ने 2026 की पहली छमाही में मजबूती दिखाई है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद दुबई में वाणिज्यिक संपत्तियों के लेनदेन का मूल्य बढ़ा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2026 की पहली छमाही में दुबई के वाणिज्यिक रियल एस्टेट लेनदेन का मूल्य सालाना आधार पर 8.5 फीसदी बढ़कर 65.23 अरब दिरहम हो गया। सौदों की संख्या करीब 13 फीसदी बढ़कर 6,487 हो गई। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ऑफिस सेगमेंट के बेहतर प्रदर्शन की वजह से हुई।

रिपोर्ट के मुताबिक इस क्षेत्र में लेनदेन का मूल्य करीब 200 फीसदी बढ़कर 15.81 अरब दिरहम हो गया। ऑफिस सेगमेंट में लेनदेन की संख्या भी सालाना आधार पर 38 फीसदी बढ़कर 2,571 हो गई। वहीं, ऑफिस की औसत कीमत 85 फीसदी बढ़कर 3,202 दिरहम प्रति वर्ग फुट पहुंच गई।

एनारॉक समूह में खुदरा और यूरोप, पश्चिम एशिया और अफ्रीका के मुख्य कार्य अधिकारी ने कहा कि यह प्रमुख कारोबारी जिलों और फ्री जोन में सीमित आपूर्ति के बीच ग्रेड-ए ऑफिस स्पेस की बढ़ती मांग को दर्शाता है। खुदरा संपत्तियों के कारोबार में भी तेज बढ़ोतरी देखी गई। लेनदेन की संख्या सालाना आधार पर 56 फीसदी बढ़कर 853 हो गई।

टाटा संस एजीएम स्थगित- जल्द होगा अगली बैठक का ऐलान

मुंबई।

टाटा संस को अभूतपूर्व स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मंगलवार को उसकी सालाना आम बैठक (एजीएम) आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या (कोरम) पूरी न होने के कारण स्थगित की गई। कंपनी के 1917 में स्थापित होने के बाद से यह पहली बार है कि उसकी एजीएम न छूटी है और न ही स्थगित हुई है, जिससे समूह के नेतृत्व को लेकर पहले से बनी अनिश्चितता और बढ़ गई है।

एजीएम स्थगन का मुख्य कारण सर रतन टाटा ट्रस्ट्स (एसआरटीटी) पर महाराष्ट्र चैरिटी कमिश्नर द्वारा इस साल की शुरुआत में लगी रोक थी, जिससे इसके नामित निदेशकों की भागीदारी प्रभावित हुई। सूत्रों के अनुसार, टाटा संस का बोर्ड अब जल्द ही, संभवतः एक सप्ताह के भीतर, बैठक बुलाएगा।

इसमें स्थगित हुई एजीएम की नई तारीख तय होगी और मौजूदा कानूनी गतिरोध के समाधान पर वरिष्ठ विशेषज्ञों की सलाह ली जाएगी।

इस संभावित बैठक में चेयरमैन एन.चंद्रशेखरन के 12 अगस्त के पत्र पर भी चर्चा होने की उम्मीद की जा रही है, जिसमें उन्होंने कहा था कि वे 20 फरवरी 2027 को अपना दूसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए खुद को आगे नहीं रखने वाले है। हालांकि, एक सूत्र के मुताबिक, बोर्ड इस बैठक में अपनी पहले की राय दोहरा सकता है कि चंद्रशेखरन को एक और कार्यकाल मिलना चाहिए। मंगलवार को एजीएम के लिए चेयरमैन चंद्रशेखरन और कुछ बोर्ड सदस्य मुंबई में मौजूद थे, जबकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा सहित कई अन्य निदेशक ऑनलाइन शामिल हुए थे।

परंतु, कोरम पूरा न होने से बैठक शुरू होने के कुछ ही समय बाद स्थगित कर दी गई।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

शाहीन शाह अफरीदी ने वनडे में पहली बार झटके 7 विकेट

नई दिल्ली, एजेंसी। पाकिस्तान की टेस्ट टीम तो इंग्लैंड के दौरे पर है. मगर उस टीम से बाहर चल रहे शाहीन शाह अफरीदी के पुराने तेवर लगता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में लौट चुके हैं. ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के घरेलू वनडे टूर्नामेंट में जब मैटर सबसे बड़ा दिखा, तो शाहीन वहां शहंशाह की तरह अपनी टीम के लिए खड़े दिखे. उन्होंने नेशनल चैंपियंस कप के फाइनल में ना सिर्फ हैट्रिक ली है, बल्कि गेंद से ऐसी आग बरसाई कि वनडे करियर का बेस्ट प्रदर्शन ही कर डाला. नतीजा, ये हुआ कि उनकी टीम टूर्नामेंट की चैंपियन बन गई.

शाहीन अफरीदी ने टीम को फ्रंट से किया लीड

नेशनल चैंपियंस कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान गोल्ड और पाकिस्तान ग्रीन की टीमें आमने-सामने थी. इस मुकाबले में शाहीन अफरीदी पाकिस्तान गोल्ड के कप्तान थे.उनकी टीम ने पहले बैटिंग की और 50 ओवर में 340 रन बनाए. मतलब बल्लेबाजों ने अपना काम कर दिया था. अब बारी गेंदबाजों की थी. स्ट्राइक गेंदबाज होने के नाते कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने इस काम में अपनी टीम पाकिस्तान गोल्ड को फ्रंट से लीड किया.

टीम को बनाया चैंपियन

शाहीन ने गेंद से उगली आग!

पाकिस्तान ग्रीन के सामने पहले से ही 341 रन जैसा बड़ा लक्ष्य था. मगर उसे और भी विकराल बना दिया शाहीन शाह अफरीदी की आग उगलती और विरोधी बल्लेबाजों से सवाल पूछती शाहीन की गेंदों ने. पाकिस्तान ग्रीन के बल्लेबाजों के पास शाहीन की गेंदों का कोई जवाब नहीं था. ऐसे में वो बस एक-एक दम उनके आगे दम तोड़ते दिखे.

शाहीन अफ्रीदी की हैट्रिक

शाहीन अफरीदी की हैट्रिक में पाकिस्तान ग्रीन के जो बल्लेबाज फंसे, उनमें मेहरान मुमताज, सलमान मिर्जा और मोहम्मद हसनेन का विकेट शामिल रहा. शाहीन के इस हैट्रिक के साथ ही पाकिस्तान ग्रीन की पारी का भी अंत हो गया.

टीम को चैंपियन बनाकर हीरो बने शाहीन अफरीदी

शाहीन शाह अफरीदी ने नेशनल चैंपियंस कप के फाइनल में अपने वनडे यानी लिस्ट ए करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 8.3 ओवर में 36 रन देकर कुल 7 विकेट लिए और अपनी टीम पाकिस्तान गोल्ड को चैंपियन बनाया. 341 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान ग्रीन पूरे 50 ओवर भी बैटिंग नहीं कर सकी और 37.3 ओवर में सिर्फ 239 रन पर ऑल आउट हो गई. इस तरह पाकिस्तान गोल्ड ने फाइनल मुकाबला 101 रन के बड़े अंतर से जीत लिया, जिसके हीरो खुद उसके कप्तान शाहीन शाह अफरीदी बने.

पहले 6 ओवर में 3 विकेट, फिर अगली 15 गेंदों में 4 विकेट

शाहीन अफरीदी ने नेशनल चैंपियंस कप के फाइनल में डाले अपने पहले 6 ओवर में 29 रन देकर 3 विकेट लिए. लेकिन, इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान ग्रीन का और बुरा हाल किया. वो और भी ज्यादा मानो खतरनाक हो गए. उन्होंने अगली 15 गेंदों पर 7 रन देकर 4 और विकेट लिए, जिसमें हैट्रिक भी शामिल रही.

संक्षिप्त समाचार

जब गोल्ड जीतने पर राष्ट्रगान बजा, वह पल शानदार था

एरोबिक जिम्नास्टिक्स में इतिहास रचने के बाद अरिहा ने साझा किए अनुभव

मुंबई, एजेंसी। भारतीय एयरोबिक जिम्नास्ट अरिहा पंगमबम ने कुछ हफ्तों पहले एशियन एयरोबिक जिम्नास्टिक्स चैंपियनशिप में ऐतिहासिक गोल्ड मेडल जीता था, जिसके साथ वह एशियन चैंपियनशिप में सीनियर महिला व्यक्तिगत श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनीं। फिलीपींस में हुए फाइनल में उन्होंने 19.100 अंक हासिल किए, जिसमें आर्टिस्ट्री (कलात्मकता) में 8.650, एग्जीक्यूशन (प्रदर्शन) में 7.600 और डिफिकल्टी (कठिनाई) में 2.850 अंक शामिल थे। इस उपलब्धि के बाद अरिहा ने कहा, जब मुझे यह गोल्ड मेडल मिला, तो वह पल बहुत शानदार था। मैं इसे शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती। जब मैंने पोडियम पर अपने देश का राष्ट्रगान बजते हुए सुना, तो उस पल मुझे गर्व भी महसूस हुआ क्योंकि मैं कुछ हासिल कर पाई थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए। वह बहुत शानदार अनुभव था और मैं उस समय बहुत खुश थी।

22 वर्षीय जिम्नास्ट ने कहा, हम डबल फ्लेक्स फ्लोर, यानी लकड़ी का फ्लोर इस्तेमाल करते हैं। भारत में उत्तराखंड में एक फ्लोर है जो हमें नेशनल गेम्स के दौरान मिला था, लेकिन दुर्भाग्य से, न सिर्फ मैं, बल्कि पूरे भारत के ज्यादातर जिम्नास्ट उस पर ट्रेनिंग भी नहीं कर पाए। हम आमतौर पर रबड़ इंटरलॉकिंग मैट पर ट्रेनिंग करते हैं, इसलिए सिर्फ एक दिन में तालमेल बिठाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रतियोगिता से पहले हमें खुद को ढालने के लिए एक दिन की पोडियम ट्रेनिंग दी जाती है, इसलिए हममें से ज्यादातर जिम्नास्ट को मुश्किल होती है, क्योंकि हमें उस फ्लोर पर कभी ठीक से ट्रेनिंग करने का मौका नहीं मिला। यही वह मुश्किल थी जिसका हमने सामना किया।

World Championship

बिना मैच खेले ही प्री क्वार्टरफाइनल में पहुंचे सात्विक-चिराग

नई दिल्ली, एजेंसी। सात्विक-चिराग की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दिलचस्प बात यह है कि इस भारतीय जोड़ी ने अब तक टूर्नामेंट में अपना अभियान शुरू नहीं किया है। सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। सात्विक-चिराग को शुरुआती मैच में वॉकओवर मिला था।

पांचवीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी विश्व चैंपियनशिप में दो कांस्य पदक जीत चुकी है। पहले दौर में बाई मिलने के बाद सात्विक-चिराग को दूसरे दौर में स्कॉटलैंड के एलेक्सजेंडर डुन और एडम प्रिंजल का सामना करना था। हालांकि, स्कॉटलैंड की जोड़ी आखिरी मिनटों में हट गई जिससे सात्विक-चिराग बिना मैच खेले ही राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए।

मानव सुथार-पडिकल बने जीत के हीरो

इंडिया-श्रीलंका टेस्ट

सीरीज में 1-0 की बढ़त

गॉल में टीम इंडिया की महाजीत

भारत 600वें टेस्ट में जीता

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत ने श्रीलंका को 165 रन से हराकर अपना 600वां टेस्ट जीत लिया है। गॉल में 372 रन के टारगेट का पीछा कर रही श्रीलंकाई टीम दूसरी पारी में 206 रन पर ऑलआउट हो गई। पहले टेस्ट में भारत की जीत के हीरो मानव सुथार रहे। उन्होंने मैच में 10 विकेट लिए। राजस्थान के सुथार ने दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट लेकर श्रीलंका की पारी समेट दी। पहले उन्होंने सोनल दिनूषा को 84 रन पर आउट किया, फिर प्रभात जयसूर्या को पहली गेंद पर बोल्ड किया और अगली गेंद पर लहिरू कुमारा को ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। भारत ने पहली पारी में 462 रन बनाए थे। देवदत्त पडिक्कल ने 167 रन की पारी खेली। जवाब में श्रीलंका 284 रन पर ऑलआउट हुआ। भारत ने दूसरी पारी में 193 रन बनाए और श्रीलंका को 372 रन का टारगेट दिया। भारत ने गॉल टेस्ट में श्रीलंका को 165 रन से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। श्रीलंका की दूसरी पारी 77.4 ओवर में 206 रन पर सिमट गई। मानव सुथार ने केशरा नुवान्था को बोल्ड कर श्रीलंका की पारी खत्म की और मैच में 10 विकेट पूरे किए।

श्रीलंका 165 रन से हारा
मानव सुथार ने मैच में 10 विकेट लिए
देवदत्त पडिक्कल का शतक

सुथार ने एक ओवर में 3 विकेट लिए

मानव सुथार ने श्रीलंका की दूसरी पारी के 75वें ओवर में 3 विकेट लेकर मैच का रुख भारत के पक्ष में कर दिया। उन्होंने पहले सोनल दिनूषा को 84 रन पर आउट किया। इसके बाद सुथार ने प्रभात जयसूर्या को पहली ही गेंद पर बोल्ड किया और अगली गेंद पर लाहिरू कुमारा को विकेटकीपर ऋषभ पंत के हाथों कैच कराया। यह टेस्ट में सुथार का लगातार दूसरे मैच में दूसरा 5 विकेट हॉल है।

Football

क्या 2026 विश्व कप की सनसनी केप वर्डे से भिड़ेगी भारतीय टीम?

सितंबर-अक्तूबर में दौरा प्रस्तावित

नईदिल्ली, एजेंसी। भारत सितंबर-अक्तूबर के बीच केप वर्डे की मेजबानी कर सकता है, दोनों टीमों के बीच दोस्ताना मुकाबले की बातचीत जारी है। केप वर्डे ने 2026 फीफा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए पहली बार नॉकआउट दौर में जगह बनाई थी। भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए आने वाले महीनों में एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक, भारत सितंबर के अंत से अक्तूबर की शुरुआत के बीच हाल में 2026 फीफा विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली केप वर्डे की मेजबानी कर सकता है। प्रस्तावित मुकाबला 30 सितंबर से 6 अक्तूबर के बीच खेले जाने की संभावना है। हालांकि, मैच की तारीख और आयोजन स्थल को लेकर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। 'बातचीत जारी है, लेकिन अभी इसे अंतिम रूप नहीं दिया गया है। हालांकि, इस बात की काफी संभावना है कि भारत 30 सितंबर से 6 अक्तूबर के बीच केप वर्डे की मेजबानी करेगा।'

सूत्र ने कहा, 'मैच का आयोजन स्थल और तारीख आधिकारिक तौर पर फैसला होने के बाद तय किए जाएंगे। इससे जुड़ी प्रक्रियाएं और विचार-विमर्श जारी हैं। उम्मीद है कि जल्द ही इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा।'

'विराट बस एक फोन कॉल दूर हैं'

नई दिल्ली, एजेंसी। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जॉर्डन कॉक्स ने विराट कोहली के साथ बिताए समय और उनसे मिली सीख को लेकर बड़ा खुलासा किया है. कॉक्स ने बताया कि कोहली उनके लिए सिर्फ एक महान क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक मेंटर की तरह रहे हैं. जब भी उन्हें किसी सलाह या मदद की जरूरत होती है, विराट हमेशा फोन के दूसरी तरफ मौजूद रहते हैं. जॉर्डन कॉक्स आईपीएल में आरसीबी टीम का हिस्सा हैं. कॉक्स ने बताया कि उन्होंने विराट कोहली के साथ करीब चार महीने भारत में बिताए.

इस दौरान वह कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करने और उनके अनुभव से सीखने में सक्षम रहे. हालांकि कॉक्स ने दोनों के बीच हुई हर बातचीत का खुलासा नहीं किया, लेकिन डेब्यू से पहले कोहली की दी गई सलाह को उन्होंने बेहद खास बताया।

दिल्ली प्रीमियर लीग :

सार्थक नंबर 1

यस ढुल को छोड़ा पीछे, दिल्ली प्रीमियर लीग में छठा पचासा

नई दिल्ली, एजेंसी। दिल्ली प्रीमियर लीग 2026 में सांसद पप्पू यादव के क्रिकेटर बेटे सार्थक रंजन का तूफान जारी है। इस लीग के अपने 7वें मैच में सार्थक ने छठी बार अर्धशतक ठोका है। वहीं वह यश ढुल को पीछे छोड़ते हुए टूर्नामेंट के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। आईपीएल 2026 में केकेआर के स्क्वाड का हिस्सा रहे सार्थक रंजन को एक भी मैच में जगह नहीं मिली थी।

अब इस फॉर्म से उन्होंने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। सार्थक ने पुरानी दिल्ली के खिलाफ 32वें मैच में 51 गेंद पर 78 रन बनाए, जिसमें 6 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उनकी शानदार पारी के बावजूद उनकी टीम नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स को जीत नहीं मिल पाई। इस मैच में 20 रन से जीत के साथ पुरानी दिल्ली 6 ने अंकतालिका में दूसरे स्थान पर जगह बना ली। सार्थक रंजन ने 100, 64, 95, 65, 57, 59, 10, 78 की पारियां अब तक खेली हैं। वहीं दिन के दूसरे मुकाबले में पहले से ही प्लेऑफ में पहुंच चुकी सेंट्रल दिल्ली किंग्स ने ईस्ट दिल्ली राइडर्स को 30 रन से मात दी। इस मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली के दोनों इन फॉर्म ओपनर्स सिद्धार्थ जून और यश ढुल खाता भी नहीं खोल सके।

सिनसिनाटी ओपन:

सबालेंका, एंड्रीवा, और गॉफ ने चौथे राउंड में जगह बनाई

सिनसिनाटी, एजेंसी। आर्यना सबालेंका ने सिनसिनाटी ओपन के चौथे राउंड में जगह बना ली है। सबालेंका ने 54 मिनट तक चले मुकाबले में सबालेंका ने वांग शिन्यु को 6-1, 6-3 से हराया। इस जीत के साथ, सबालेंका अब अपने करियर में 45 डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट्स में राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई हैं। उनकी इस जीत ने सिनसिनाटी में जीत के मामले में उन्हें सक्रिय खिलाड़ियों में सबसे आगे कर दिया है। सबालेंका के नाम अब डब्ल्यूटीए 1000 इवेंट्स में 50 करियर जीत है। सबालेंका 2009 में इस फॉर्मेट के शुरू होने के बाद से ऐसा करने वाली सेरेना विलियम्स (104) और इगा स्वियाटेक (58) के बाद तीसरी खिलाड़ी हैं।

इस बीच, नंबर 5 सीड मीरा एंड्रीव नंबर 32 सीड जेनिस त्जेन को हराकर चौथे राउंड में पहुंच गईं। एंड्रीव ने 1 घंटे 42 मिनट तक चले इस मैच में 6-1, 7-6(5) से जीत दर्ज की। एंड्रीवा, जो 2024 में टूर्नामेंट में अपनी पिछली एकमात्र उपस्थिति में सिनसिनाटी में क्वार्टर फाइनलिस्ट थीं, ने जून में रोलैंड गैरोस में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद पहली बार लगातार मैच जीते हैं।

अब उनका सामना इस साल चौथी बार नंबर 10 सीड मार्टा कोस्त्युक से होगा। कोस्त्युक उनके हेड-टू-हेड में 2-1 से आगे हैं, हालांकि पिछली मुलाकात में एंड्रीवा ने रोलैंड गैरोस सेमीफाइनल में कोस्त्युक को हराया था। 2023 की चैंपियन कोको गॉफ ने भी साथी अमेरिकन एन ली पर 6-1, 7-6 (3) से जीत हासिल करके 2026 सिनसिनाटी ओपन के चौथे राउंड में अपनी जगह पक्की कर ली।

गॉफ अब अपने करियर के 36वें डब्ल्यूटीए 1000 चौथे राउंड में हैं, जिसमें इस सीजन के छह शामिल हैं। सिनसिनाटी एकल में हिस्सा लेने वाले सक्रिय खिलाड़ियों में सिर्फ एरिना सबालेंका (44), कैरोलिन प्लिसकोवा (44), एलिना स्वितोलिना (43), इगा स्वियाटेक (38) और जेसिका पेगुला (38) के नाम उनसे ज्यादा हैं।

संक्षिप्त समाचार

नेपाल में सनातन धर्म को राष्ट्रीय पहचान बनाने की मांग, पूर्व पीएम देउबा के बयान से क्यों गरमाई सियासत

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने देश की राष्ट्रीय पहचान को सनातन धर्म से जोड़ने की बात कही है। उनके नेतृत्व वाले नेपाली कांग्रेस गुट के 14वें राष्ट्रीय सम्मेलन में इस दिशा में आगे बढ़ने का प्रस्ताव पारित किया गया। इससे नेपाल को फिर से हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग को राजनीतिक ताकत मिलने की चर्चा शुरू हो गई है। देउबा ने सम्मेलन के समापन समारोह में खुद को हिंदू बताते हुए अपनी राजनीतिक सोच भी साफ की। पारित प्रस्ताव केवल हिंदू धर्म तक सीमित नहीं है। इसमें सनातन धर्म के साथ हिंदू, बौद्ध और किरात परंपराओं के संरक्षण पर जोर दिया गया है। साथ ही सभी धर्मों और समुदायों की धार्मिक आजादी, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने की बात कही गई है। यानी प्रस्ताव में नेपाल की पारंपरिक धार्मिक पहचान को मजबूत करने के साथ दूसरे समुदायों के अधिकारों की बात भी शामिल है। नेपाली कांग्रेस के दूसरे गुट ने सम्मेलन में पारित प्रस्तावों और दिए गए बयानों पर आपत्ति जताई है। पार्टी प्रवक्ता विनोद चालिसे ने कहा कि सम्मेलन में हुए काम और नेताओं के बयानों पर पार्टी की नजर है। इससे साफ है कि सनातन धर्म और राष्ट्रीय पहचान का मुद्दा केवल नेपाल की व्यापक राजनीति में ही नहीं, बल्कि नेपाली कांग्रेस के भीतर भी मतभेद का कारण बन सकता है।

लहरों में फंसे भारतीय मूल के बच्चे को बचाने वाले 16 साल के किशोर से मिले ट्रंप, किया सम्मानित; मामला क्या

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में 25 जुलाई को 10 वर्षीय भारतीय मूल का बच्चा नाथनियल राय समुद्र की तेज लहरों में फंस गया था। वह सांता क्रूज के सीब्राइट बीच पर पानी में था। इसी दौरान उसने अपना संतुलन खो दिया और लहरों की चपेट में आ गया। वहां ड्यूटी पर मौजूद 16 वर्षीय लाइफगार्ड राइडर विलियम्स ने बच्चे को मुश्किल में देखा और तुरंत उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। विलियम्स ने बताया कि उसने बच्चे को लाइफगार्ड टावर से करीब 20 गज दूर टखने तक पानी में अपना संतुलन खोते देखा था। खतरा समझते ही वह उसकी तरफ दौड़ा। उसने कहा कि ऐसे मुश्किल समय में लाइफगार्ड अपनी ट्रेनिंग पर भरोसा करते हैं। उसका पूरा ध्यान बच्चे को जितनी जल्दी हो सके पानी से बाहर निकालने पर था। बचाव की यह घटना कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बचाव का वीडियो सामने आने के बाद ट्रंप की भी इस घटना पर नजर पड़ी। उन्होंने लाइफगार्ड विलियम्स और उसके परिवार को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया।

खूंखार आतंकी संगठन अल-शबाब का हमला नाकाम, सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 30 आतंकी ढेर

जाम्बिया, एजेंसी। अफ्रीकी देश जाम्बिया में राष्ट्रपति हकाइंदे हिचिलेमा दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए हैं। जाम्बिया के निर्वाचन आयोग ने 18 अगस्त, 2026 को इसकी घोषणा की। उन्हें 14 अगस्त को हुए राष्ट्रपति चुनाव का सीधा विजेता घोषित किया गया। हिचिलेमा ने 51 फीसदी से अधिक वोट हासिल किए। आयोग के अनुसार, हिचिलेमा को 2,965,326 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी ब्रायन मुंडुबिले को 1,856,217 वोट प्राप्त हुए। आयोग की अध्यक्ष म्वांगाला ज़ालूमिस ने हिचिलेमा को राष्ट्रपति-निर्वाचित घोषित किया। मतगणना 15 अगस्त को मतदान अधिकारियों पर हमले और मतपत्रों की चोरी के कारण निलंबित हुई, फिर कड़ी सुरक्षा में शुरू की गई।

बिग बेंड नेशनल पार्क में सीमा नहीं बनेगी, ट्रंप प्रशासन ने विवादित परियोजना रोकी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन ने बिग बेंड नेशनल पार्क में एक विवादास्पद सीमा परियोजना का निर्माण अस्थायी रूप से रोक दिया है। यह निर्णय एजेंसी प्रमुख के टेक्सास दौरे के बाद जमीनी मूल्यांकन के लिए लिया गया है। यह परियोजना दक्षिणी टेक्सास में राष्ट्रीय पार्क से होकर गुजरनी थी। इस परियोजना को आलोचकों के कड़े द्विदलीय विरोध का सामना करना पड़ा है। आलोचकों का कहना है कि यह क्षेत्र एक प्राचीन पर्यावरणीय इलाका है। उनके अनुसार, यह परियोजना इस क्षेत्र को खराब कर रही है। उनका तर्क है कि क्षेत्र का कठिन और दूरस्थ इलाका पहले से ही प्रवासियों और तस्करों को रोकता है।

दक्षिण कोरिया को छोड़ उत्तर कोरिया के करीब क्यों जा रहे ट्रंप अमेरिका के सहयोगियों की बढ़ी चिंता

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों को कम करने का फैसला किया है। इससे केवल लंबे समय से अमेरिका के सहयोगी रहे दक्षिण कोरिया को ठेस नहीं पहुंची है, बल्कि एशिया और दुनिया के दूसरे हिस्सों में अमेरिका के सुरक्षा हितों को लेकर भी बड़ी चिंताएं पैदा हो गई हैं।

ट्रंप ने अपने फैसले की वजह बताते हुए कहा कि दक्षिण कोरिया ने ईरान के खिलाफ उनकी लड़ाई में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने अलग-थलग रहने वाले उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन के साथ अपने अच्छे संबंधों का भी जिक्र किया। ट्रंप अक्सर विदेश नीति में फायदे-नुकसान और व्यक्तिगत रिश्तों को ज्यादा अहमियत देते रहे हैं। यही उनके राष्ट्रपति कार्यकाल की एक खास पहचान रही है।

जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के राष्ट्रपति कार्यकाल में यूरोपीय मामलों के सहायक विदेश मंत्री रह चुके डैन फ्राइड ने कहा, मुझे इसमें अमेरिका का कोई हित नजर नहीं आता। किसी भी स्तर पर यह समझ में नहीं आता। इससे दक्षिण कोरिया कमजोर होता है, जापान कमजोर होता है, ताइवान डरता है, नाटो चिंतित होता है और चीन को हौसला मिलता है। इतना ही नहीं, उत्तर कोरिया का भी हौसला बढ़ता है। ओबामा प्रशासन में पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र के सहायक विदेश मंत्री रह चुके डैनी रसेल ने कहा कि उत्तर

कोरिया के पक्ष में ट्रंप का फैसला ऐसी श्रेणी में आता है, जिसमें यह समझना मुश्किल है कि इससे स्थिति और खराब कैसे हो सकती है। उत्तर कोरिया हर साल होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों का कड़ा विरोध करता है। उन्होंने कहा, यह दुखद रूप से पूरी तरह उलटा है। ट्रंप एक सहयोगी को सजा दे रहे हैं और एक विरोधी को बढ़ावा दे रहे हैं। न्यूयॉर्क के एशिया सोसाइटी पॉलिसी इंस्टीट्यूट से जुड़े रसेल ने कहा, ट्रंप अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सुरक्षा की कीमत पर किम जोंग उन को नाराज होने से बचा रहे हैं।

दक्षिण कोरिया को इससे क्या संदेश जाता है : रविवार को ट्रंप ने अमेरिकी सेना को 11 दिन चलने वाले उलची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास का आकार छोटा करने का आदेश दिया। यह सैन्य अभ्यास सोमवार को तय समय पर शुरू हो गया। हालांकि, यह साफ नहीं था कि अभ्यास के किन-किन हिस्सों को कम किया जाएगा। ट्रंप के इस एलान से दक्षिण कोरिया में बहुत से लोग आश्चर्यचकित रह गए। दक्षिण कोरिया दशकों से अमेरिका का करीबी सहयोगी रहा है। वहां राष्ट्रीय सुरक्षा को बेहद अहम माना जाता है, क्योंकि उसके सामने परमाणु हथियार रखने वाले उत्तर कोरिया का खतरा मौजूद है।

अमेरिकी कांग्रेस (संसद) में कई डेमोक्रेट सांसदों ने भी तुरंत ट्रंप की आलोचना की। न्यूयॉर्क से डेमोक्रेट सांसद और विदेश मामलों की समिति में सबसे बड़े डेमोक्रेट नेता ग्रेग मीक्स ने एक बयान में कहा, अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक के साथ विरोधी जैसा व्यवहार करने से हमारे गठबंधन कमजोर होते हैं और चीन तथा उत्तर कोरिया को फायदा मिलता है। सोमवार को ट्रंप ने अपने फैसले का फिर समर्थन किया। उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन की फोन पर बात करते हुए एक तस्वीर पोस्ट की। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दलों के राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान काम कर चुके सेवानिवृत्त अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तर कोरिया को रोकने के लिए बेहद अहम हैं। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत से दूरी बना रखी है और उसने हथियारों का परीक्षण भी तेज कर दिया है। वुड ने कहा, हम यह भी नहीं चाहते कि दक्षिण कोरिया यह निष्कर्ष निकाले कि अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसके पास परमाणु हथियार हासिल करना ही एकमात्र गारंटी है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों तरह के प्रशासन में रक्षा और खुफिया विभाग से जुड़े पदों पर रह चुके मैथ्यू क्रोनिग ने कहा कि सर्वे बताते हैं कि दक्षिण कोरियाई लोगों में अपने परमाणु हथियार विकसित करने के विचार का समर्थन लगातार बढ़ा है। क्रोनिग ने कहा, अमेरिका दक्षिण कोरिया को यह भरोसा दिलाने के लिए बहुत मेहनत करता रहा है कि वह सुरक्षित है। अब वाशिंगटन के थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल से जुड़े क्रोनिग ने कहा कि सैन्य अभ्यासों का आकार कम करने से संभवतः इस भरोसे को नुकसान पहुंचता है।

ट्रंप को खुश करने की कोशिश कर रहा दक्षिण कोरिया : ट्रंप ने यह फैसला तब लिया, जब दक्षिण कोरिया उन्हें खुश करने और उनका समर्थन पाने की कोशिश कर रहा था। दक्षिण कोरिया व्यापार और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर अमेरिका का साथ चाहता था। पिछले साल नए राष्ट्रपति ली जे म्युंग जब ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे, तो उन्होंने सबसे पहले वहां की शानदार सजावट की तारीफ की। ओवल ऑफिस को सुनहरे रंग की सजावट से सजाया गया था। ली ने ट्रंप की इस बात का भी समर्थन किया कि अगर वह 2020 में लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बन जाते, तो किम जोंग उन परमाणु हथियार बनाने की अपनी योजना को आगे नहीं बढ़ाते। ली ने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में उत्तर कोरिया में ट्रंप टावर बनाया जा सकता है।

एफबीआई मुख्यालय अब कहां बनेगा: ट्रंप प्रशासन को कोर्ट ने दिया बड़ा झटका, हेडक्वार्टर की शिफ्टिंग पर लगाई रोक

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के एक जज ने सोमवार को एफबीआई के मुख्यालय को वॉशिंगटन की एक फेडरल ऑफिस बिल्डिंग में ले जाने की योजना पर रोक लगा दी। जज ने पाया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने मैरीलैंड में पास की गई एक नई बिल्डिंग बनाने की योजना को गैर-कानूनी तरीके से रद्द कर दिया था।

यह फैसला देश की प्रमुख कानून लागू करने वाली एजेंसी का मुख्य कार्यालय कहां बनाया जाए, इस पर बरसों से चल रही लड़ाई में एक नया घटनाक्रम है। बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान मैरीलैंड के ग्रीनबेल्ट में एक जगह चुनी गई थी, लेकिन ट्रंप की ओर से नियुक्त अधिकारियों ने पिछले साल उस फैसले को पलटने की कोशिश की।

ट्रंप प्रशासन क्या चाहता था : वे चाहते थे कि एफबीआई के मौजूदा मुख्यालय से कुछ ब्लॉक दूर स्थित फेडरल ऑफिस कॉम्प्लेक्स, रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जाए।

जिला जज चुआंग ने क्या फैसला सुनाया : राष्ट्रपति बराक ओबामा की ओर से नियुक्त अमेरिकी जिला जज थियोडोर डी. चुआंग ने फैसला सुनाया कि यह कदम कानून के मुताबिक नहीं था। उन्होंने ट्रंप प्रशासन को एफबीआई को रीगन बिल्डिंग में ले जाने के लिए उसकी मरम्मत करने या फंड का दोबारा इस्तेमाल करने से रोक दिया। मुकदमा किसने दायर किया था न्याय विभाग और एफबीआई के अधिकारियों ने टिप्पणी के अनुरोधों का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। यह मुकदमा मैरीलैंड राज्य और प्रिंस जॉर्ज काउंटी ने दायर किया था।

मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा : मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन (जो डेमोक्रेट हैं) ने एक बयान में कहा, मैरीलैंड और प्रिंस जॉर्ज काउंटी ने एफबीआई मुख्यालय हासिल करने के लिए एक दशक से ज्यादा समय तक काम किया है। इसके साथ ही करोड़ों डॉलर देने का वादा किया। एफबीआई को रीगन बिल्डिंग में ले जाने और इस प्रोजेक्ट के लिए कांग्रेस द्वारा अलग रखे गए फंड को दूसरी जगह लगाने की ट्रंप प्रशासन की गैर-कानूनी कोशिश को रोककर, कोर्ट ने ग्रीनबेल्ट लौटने का रास्ता साफ कर दिया है।

एफबीआई का मौजूदा मुख्यालय कहां है : एफबीआई का मौजूदा मुख्यालय, पेन्सिलवेनिया एवेन्यू पर स्थित जे. एडगर हूवर बिल्डिंग में 1975 में खोला गया था। मुख्यालय को दूसरी जगह ले जाने के पक्ष में तर्क देने वालों का कहना है कि ब्रूटलिस्ट-शैली की यह इमारत अब जर्जर हो चुकी है। इसके चारों ओर पैदल चलने वालों को गिरते मलबे से बचाने के लिए जाल लगे हैं। दोनों राज्यों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद, पास के वर्जीनिया के बजाय मैरीलैंड वाली जगह को चुना गया था।

भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण के दावे पर घिरे पीएम बालेन; 26 अगस्त को संसद में विपक्ष करेगा सवालों की बौछार

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह अगले सप्ताह प्रतिनिधि सभा में सांसदों के सवालों का सामना करेंगे। सदन के अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्याल ने सोमवार को बताया कि प्रधानमंत्री के साथ सीधे सवाल-जवाब का सत्र 26 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष ने सदन को बताया कि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2026 के अध्याय-9 के तहत प्रधानमंत्री के साथ प्रश्नोत्तर सत्र निर्धारित किया गया है। इस दौरान सदन में मौजूद प्रत्येक राजनीतिक दल से कम से कम एक सांसद प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकेगा। अध्यक्ष ने सांसदों से अपने सवाल संक्षिप्त रखने की अपील भी की। प्रधानमंत्री शाह के संसद में आने का फैसला ऐसे समय हुआ है, जब विपक्ष लंबे समय से उनके एक बयान पर स्पष्टीकरण की मांग कर रहा है। दरअसल, 31 मई को संसद में अपने पहले संबोधन के दौरान शाह ने कहा था कि उन्हें इस बारे में जानकारी मिली है कि नेपाल ने भारत के क्षेत्र में भी 'अतिक्रमण' किया है। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने प्रधानमंत्री से इस बयान को स्पष्ट करने की मांग की। उनका कहना है कि यदि नेपाल की ओर से भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण की बात कही गई है तो प्रधानमंत्री को उसके समर्थन में सबूत पेश करने चाहिए या फिर अपना बयान वापस लेना चाहिए। विपक्ष की लगातार मांगों के बाद प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष डोल प्रसाद आर्याल ने प्रधानमंत्री को सदन में उठाए गए सवालों का जवाब देने के लिए कहा। संसद सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, अध्यक्ष ने उन मुद्दों पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है जो उनके अधिकार क्षेत्र से जुड़े हैं। आर्याल ने कहा कि सांसद लंबे समय से प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण विषयों और उनके अधिकार क्षेत्र से जुड़े मामलों पर सवालों का जवाब देने की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के बयान के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने उसकी अलग व्याख्या पेश की थी। मंत्रालय ने कहा था कि शाह की टिप्पणी दोनों देशों के बीच 'नो-मैन्स लैंड में अतिक्रमण' और 'सीमा पार कब्जे' से जुड़ी थी, न कि किसी क्षेत्र पर औपचारिक दावा करने के संदर्भ में। इसके बावजूद विपक्षी सांसद प्रधानमंत्री से सदन में सीधे स्पष्टीकरण की मांग करते रहे।

दो बंदूकें लेकर स्कूल पहुंचा छात्र, पहले टीचर पर चलाई गोली फिर साथी छात्र की हत्या कर की खुदकुशी

मनीला, एजेंसी। दक्षिणी फिलीपींस में एक हाई स्कूल में मंगलवार को दो बंदूकें लिए एक छात्र ने अपने ही एक साथी छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद फिर खुदकुशी कर ली। इस घटना के बाद सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।

जाम्बोआंगा शहर के मेयर खाइमर अदान ओलासो ने कहा कि हमलावर ने शायद हमले की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिए बॉडी कैमरा पहना हुआ था। यह हमला उनके शहर में एटेनिओ डी जाम्बोआंगा यूनिवर्सिटी कैंपस के हाई स्कूल में हुआ। उन्होंने बताया कि दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं।

मेयर ने क्या बताया : ओलासो ने रेडियो नेटवर्क को बताया कि हमलावर ने पहले एक टीचर पर गोली चलाई, लेकिन यह साफ नहीं है कि टीचर को

गोली लगी या नहीं। इसके बाद उसने अपने एक साथी छात्र को गोली मारी, जिससे उसकी मौत हो गई, और फिर उसने खुद को गोली मार ली।

छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया : हाई स्कूल की बिल्डिंग में गोली चलने की आवाज के बाद सैकड़ों छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। यह बिल्डिंग एक सुरक्षित कैंपस में है, जो कैथोलिक यूनिवर्सिटी के बड़े कैंपस से अलग है। उस बड़े कैंपस में यूनिवर्सिटी के कॉलेज और प्रोफेशनल स्कूल हैं, जो जाम्बोआंगा बंदरगाह शहर में स्थित हैं।

पुलिस ने क्या कहा : गोलीबारी के कुछ घंटों बाद पुलिस ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने छात्रों के माता-पिता और अभिभावकों से शांत रहने और बच्चों को ले जाने के लिए हाई स्कूल की सलाह और व्यवस्थाओं का पालन करने को कहा।

पुलिस ने जनता से क्या अपील की : नेशनल पुलिस चीफ जनरल जोस मेलेंसियो नार्टाटेज जूनियर ने कहा, अधिकारी अभी घटना से जुड़ी परिस्थितियों का पता लगा रहे हैं। पुलिस सही समय पर पक्की जानकारी देगी और जनता से अपील करती है कि वे ऐसी बिना पुष्टि वाली खबरें, तस्वीरें या वीडियो शेयर न करें जिनसे बेवजह चिंता पैदा हो सकती है। नार्टाटेज ने कहा, नेशनल पुलिस जनता को भरोसा दिलाती है कि स्कूल समुदाय की सुरक्षा और भलाई हमारी प्राथमिकता है। हम स्कूल प्रशासन, माता-पिता, अभिभावकों और समुदाय का उनके धैर्य, सहयोग और समझदारी के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि अधिकारी स्थिति को संभालने का काम कर रहे हैं। यह गोलीबारी तब हुई जब पुलिस ने भरोसा दिलाया था कि देश भर के स्कूलों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इससे पहले जून में मध्य टैकलोबन शहर में हुई गोलीबारी में तीन हाई स्कूल छात्र मारे गए थे और कम से कम 20 अन्य घायल हुए थे। पुलिस ने उस गोलीबारी को अंजाम देने के आरोप में 14 और 15 साल के दो छात्रों को गिरफ्तार किया था। फिलीपींस में बंदूक के इस्तेमाल से जुड़े अपराध आम हैं, जिसका एक कारण बिना लाइसेंस वाली बंदूकों का बड़ी संख्या में होना है, लेकिन स्कूलों में गोलीबारी की घटनाएं अपेक्षाकृत कम होती हैं।

बच्चों को अकेले खेलने की आजादी पर अमेरिका में बदली सोच, देश के 13 राज्यों ने क्यों दी कानून में ढील

इयान फ्रिश, एजेंसी। अमेरिका में बच्चों की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से बनाए गए सख्त नियमों पर अब बहस तेज हो रही है। कई जगह अभिभावकों को बच्चों को अकेले पार्क भेजने, आसपास खेलने देने या छोटी दूरी पर अकेले जाने देने पर कार्रवाई का डर रहता था। अब इस सोच में बदलाव दिखाई दे रहा है। 13 अमेरिकी राज्यों ने बाल-उपेक्षा से जुड़े नियमों में ढील दी है, ताकि बच्चों को उम्र के हिसाब से कुछ स्वतंत्रता देने पर माता-पिता को कानूनी कार्रवाई का सामना न करना पड़े। अटलांटा में एक छह साल के बच्चे के अकेले पार्क में खेलने का मामला इस बहस का उदाहरण बना। बच्चे को पार्क में अकेले देखकर एक महिला ने बाल

कल्याण विभाग में उसके माता-पिता के खिलाफ शिकायत कर दी। इसके बाद मैलरी शर्ली और उनके पति क्रिस्टोफर प्लेसेंट्स से पूछताछ हुई। लंबी कानूनी प्रक्रिया और अपील के बाद दंपती को आरोपों से बरी कर दिया गया। इस मामले ने सवाल खड़ा किया कि बच्चों की सुरक्षा और उन्हें स्वतंत्रता देने के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।

13 राज्यों ने नियमों में ढील क्यों दी : अमेरिका में फ्री-रेंज किड्स आंदोलन को मिल रहे समर्थन के बीच 13 राज्यों ने अपने बाल-उपेक्षा कानूनों में बदलाव किया है। इसका मकसद यह स्पष्ट करना है कि बच्चों को उनकी उम्र और समझ के मुताबिक अकेले बाहर खेलने या आसपास जाने की अनुमति देना अपने आप में उपेक्षा नहीं माना जाए। समर्थकों का तर्क है कि बच्चों को हर समय निगरानी में रखने के बजाय सीमित स्वतंत्रता देना उनके आत्मविश्वास और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत कर सकता है। बच्चों की स्वतंत्रता को लेकर सोच में बदलाव के बीच आंकड़े भी दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। द ब्रिटिश चिल्ड्रन प्ले सर्वे के अनुसार, पिछली पीढ़ी के बच्चों को औसतन 8.9 वर्ष की उम्र में अकेले बाहर खेलने की अनुमति मिल जाती थी। आज यह उम्र बढ़कर औसतन 10.7 वर्ष हो गई है। यानी बच्चों को स्वतंत्र रूप से बाहर जाने की अनुमति अब करीब दो साल देर से मिल रही है। वहीं करीब 34 फीसदी बच्चे स्कूल के बाद बाहर खेलने नहीं जाते हैं। बच्चों के लिए खेलना केवल मनोरंजन नहीं है। इससे उनका शारीरिक विकास होता है और वे दूसरे बच्चों के साथ बातचीत करना, छोटे फैसले लेना और परिस्थितियों को समझना सीखते हैं। आंकड़ों के मुताबिक, पांच से 17 वर्ष की उम्र के बच्चों को रोज करीब 60 मिनट खेलना-कूदना चाहिए।

भारत के चुनावी मॉडल के मुरीद हुए ट्रंप, अमेरिका में वोटर आईडी अनिवार्य करने की मांग क्यों हुई तेज

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की चुनाव व्यवस्था का उदाहरण देते हुए अमेरिका में हर मतदाता के लिए फोटो पहचान पत्र अनिवार्य करने की अपनी मांग फिर दोहराई है। ट्रंप ने दावा किया कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने उनके प्रशासन से सवाल किया था कि अमेरिका में वैध फोटो पहचान पत्र के बिना चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं। ट्रंप ने भारत की व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिका को भी चुनाव में पहचान और नागरिकता से जुड़े नियम कड़े करने चाहिए।

भारत के चुनाव को लेकर ट्रंप ने क्या दावा किया : ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि भारत के हालिया आम चुनाव में करीब 64.6 करोड़ लोगों ने मतदान किया और एक प्रतिशत से भी कम मतदाताओं ने डाक मतपत्र का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि हर मतदाता के लिए वैध फोटो पहचान पत्र जरूरी था। ट्रंप ने भारत के चुनावी मॉडल को अमेरिका में अनिवार्य फोटो पहचान की जरूरत के समर्थन में उदाहरण के तौर पर पेश किया। उनका कहना है कि इससे चुनाव में धोखाधड़ी की आशंका को कम किया जा सकता है।

सेव अमेरिका एक्ट में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं : ट्रंप जिस सेव अमेरिका एक्ट के समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे हैं, उसका पूरा नाम सेफगार्ड अमेरिकन वोटर एलिजीबिलिटी एक्ट है। प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिका में मतदान के लिए पंजीकरण कराने वाले लोगों को अपनी नागरिकता का प्रमाण देना होगा। इसके अलावा देशभर में मतदाता पहचान पत्र की व्यवस्था लागू करने का प्रस्ताव है। कानून

डाक से मतदान की सुविधा पर भी कड़े प्रतिबंध लगाने की दिशा में है। ट्रंप इसे चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए जरूरी कदम बताते हैं।

क्या अमेरिका में इस कानून को लेकर सहमति है : सेव अमेरिका एक्ट को लेकर अमेरिका में राजनीतिक सहमति नहीं बन पाई है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों के भीतर इस मुद्दे पर मतभेद हैं। ट्रंप लगातार कानून पारित कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीनेट में इसे आगे बढ़ाने को लेकर अब तक ठोस कदम नहीं उठे हैं। अगस्त की शुरुआत में अमेरिकी सीनेट पांच सप्ताह के अवकाश पर चली गई थी और कानून को लेकर कोई अंतिम प्रगति नहीं हुई। ट्रंप का तर्क है कि मतदाता की पहचान और नागरिकता की पुष्टि चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता के लिए जरूरी है। भारत की चुनाव व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्होंने अमेरिका में भी ऐसे नियम लागू करने की मांग की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को चुनावी धोखाधड़ी रोकने के लिए सेव अमेरिका एक्ट पारित करना चाहिए। हालांकि, कानून को लेकर राजनीतिक मतभेद अभी कायम हैं। भारत का उदाहरण देकर ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिकी चुनाव व्यवस्था में पहचान पत्र और नागरिकता के सवाल को राजनीतिक बहस के केंद्र में ला दिया है।

इमरान खान की आंखों में कितना सुधार हुआ? जेल प्रशासन ने सेहत पर सुप्रीम कोर्ट में दी पूरी जानकारी

इस्लामाबाद, एजेंसी। पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की आंखों को लेकर जेल प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट को अहम जानकारी दी है। रावलपिंडी की अदियाला जेल की ओर से अदालत में दाखिल रिपोर्ट में कहा गया है कि इमरान खान की आंखों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और उनकी नजर अब 'लगभग सामान्य' हो गई है।

यह रिपोर्ट ऐसे समय सामने आई है, जब सुप्रीम कोर्ट में इमरान की उस याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में इलाज कराने की मांग की है। 73 वर्षीय इमरान खान अगस्त 2023 से जेल में हैं। उनकी आंख की बीमारी जनवरी के अंत में सामने आई थी। उन्हें दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन यानी सीआरवीओ की समस्या बताई गई थी। इसके बाद उन्हें इलाज के लिए इस्लामाबाद स्थित पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी पीआईएमएस कई बार ले जाया गया। जेल प्रशासन के मुताबिक, पीआईएमएस के नेत्र रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर मुहम्मद आरिफ खान और रावलपिंडी के अलशिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के विट्रियॉ-रेटिनल विशेषज्ञ डॉक्टर नदीम कुरैशी ने उनका इलाज किया।

जेल प्रशासन ने इमरान की सेहत को लेकर क्या दावा किया : जेल प्रशासन की रिपोर्ट के अनुसार, इलाज के बाद इमरान खान की आंख में काफी सुधार देखा गया और उनकी नजर लगभग सामान्य हो गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि उनकी सेहत की नियमित निगरानी की जा रही है। जेल के चिकित्सा अधिकारी दिन में तीन बार उनकी जांच करते हैं। इस दौरान उनके भोजन की निगरानी के साथ रक्तचाप, हृदय गति और ऑक्सीजन स्तर जैसे जरूरी स्वास्थ्य मानकों की भी जांच की जाती है। प्रशासन ने कहा कि जेल में रहने के दौरान उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी लगातार रखा गया है।

क्या इमरान खान को जेल में पर्याप्त इलाज मिल रहा : जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को पर्याप्त स्वास्थ्य

सुविधाएं दी जा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, अलग-अलग चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञों और डॉक्टरों ने भी दोनों की स्वास्थ्य जांच की है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट से इमरान की इलाज संबंधी याचिका को खारिज करने का अनुरोध किया है। उसका कहना है कि इमरान को जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी आंख की हालत में सुधार इसका प्रमाण है।

इमरान खान की पार्टी इस रिपोर्ट पर क्या कह रही : जेल प्रशासन के दावे के बावजूद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई की ओर से इमरान खान की सेहत को लेकर चिंता जताई गई है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि एक मेडिकल रिपोर्ट में इमरान का रक्तचाप अधिक पाया गया है। उन्होंने दावा किया कि इमरान के निजी डॉक्टरों ने पहले उनका रक्तचाप सामान्य पाया था। अफरीदी के अनुसार, इमरान के परिवार, कानूनी टीम और निजी डॉक्टरों को 2 दिसंबर 2025 से उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट में कब होगी इमरान की याचिका पर सुनवाई : इमरान खान की इलाज संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 18 अगस्त को सुनवाई होनी है। तीन सदस्यीय पीठ इसकी सुनवाई करेगी। पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति शाहिद वाहिद करेंगे। इसमें न्यायमूर्ति नईम अख्तर अफगान और न्यायमूर्ति इश्तियाक इब्राहिम भी शामिल हैं। जेल प्रशासन ने अदालत से इमरान की याचिका को खारिज करने की मांग की है। वहीं पीटीआई का कहना है कि इमरान को किसी विशेष रियायत की मांग नहीं है, बल्कि उन्हें कानून के अनुसार उचित इलाज और न्याय मिलना चाहिए।

फेंटेनाइल पर विवादास्पद रणनीति की समीक्षा, न्यू मेक्सिको ने मुकदमे की धमकी दी

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी न्याय विभाग के आंतरिक निगरानीकर्ता ने छ्रश्व्र की विवादास्पद रणनीति की समीक्षा की घोषणा की है। इस रणनीति में बड़े मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ मामले बनाने के लिए फेंटेनाइल को सड़कों पर जाने दिया गया। वर्तमान और पूर्व एजेंटों ने इसे सार्वजनिक सुरक्षा के लिए जुआ बताया है। व्हाइट हाउस ने फेंटेनाइल को सामूहिक विनाश का हथियार घोषित किया है। यह समीक्षा एसोसिएटेड प्रेस की उस जांच के बाद आई है, जिसमें छ्रश्व्र एजेंटों ने न्यू मैक्सिको में फेंटेनाइल खेपों की निगरानी की पर उन्हें जब्त नहीं किया। व्हिसलब्लोअर डेविड हॉवेल ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने न्यू मैक्सिको में 卐समुदाय को जहर दिया卐। न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज़ ने न्याय विभाग पर मुकदमा करने की धमकी दी है। दो अन्य व्हिसलब्लोअर भी सामने आए हैं।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास, भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी की माला चढ़ी हुई तस्वीर, बीजेपी ने की थाने में शिकायत

रांची (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट के विरुद्ध बीजेपी ने रांची के साइबर थाने में लिखित शिकायत की है और आरोपितों के विरुद्ध इंटरनेट मीडिया पर अमर्यादित सामग्री प्रसारित करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पर ऋषिकेश चौहान नाम के अकाउंट से पीएम मोदी के चित्र पर माला चढ़ी हुई तस्वीर व इससे जुड़ी सामग्री पोस्ट की गई है। उसमें अंतिम संस्कार से संबंधित शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है।एक जीवित प्रधानमंत्री को मृत दर्शाना अत्यंत गंभीर व आपत्तिजनक है। मीडिया रिपोर्ट अजय साह ने पुलिस से मांग की है कि संबंधित इंस्टाग्राम अकाउंट की आइपी लाग, लागिन हिस्ट्री, डिवाइस डिटेल, लिंक्ड मोबाइल नंबर, ईमेल, मेटा डाटा व अन्य डिजिटल साक्ष्य को विधि के मुताबिक सुरक्षित रखा जाए और सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की जाए। इधर, साइबर थाना रांची का कहना है कि शिकायत मिली है, उसका सत्यापन किया जाएगा और उसके बाद उस आवेदन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, पूरे मामले को संवेदनशील होकर देखा जा रहा है।

पश्चिम बंगाल में दो दिन में दो होटलों में लगी आग से 18 की मौत, मचा हड़कंप

-कई मृतक बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज कराने भारत आए थे, जांच शुरु

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में लगातार दो बड़े होटलों में अग्निकांड से हड़कंप मच गया है। कोलकाता और बीरभूम जिले के धार्मिक स्थल तारापीठ में हुई अलग-अलग आग की दुर्घटनाओं में कुल 18 लोगों की जान चली गई। पुलिस और अग्निशमन विभाग दोनों मामलों में होटल प्रबंधनों द्वारा फायर सेफ्टी नियमों के उल्लंघन की गहन जांच कर रहे हैं। होटल में ठहरे कई मेहमान बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए कोलकाता आए थे। बचाव दल मौके पर पहुंचे और इमारत से कई लोगों को बाहर निकाला। रात 3 बजे के बाद, 9 लोगों को बचाया गया और अस्पताल ले जाया गया, जहां बाद में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फायर विभाग ने बताया कि सभी मृतक बांग्लादेशी नागरिक थे जो इलाज के लिए शहर में आए थे। अधिकारी इन आरोपों की जांच कर रहे हैं कि होटल में आग से सुरक्षा के पर्याप्त उपाय और उचित इंतज़ाम नहीं थे। अधिकारियों ने अभी तक आग लगने के सही कारण का पता नहीं लगाया है। जांच जारी है। कोलकाता में आग की यह घटना बंगाल के बीरभूम ज़िले के एक होटल में लगी आग के ठीक एक दिन बाद हुई है। सोमवार को तड़के करीब 4 बजे तारापीठ में चार मंज़िला होटल के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई, जब ज़्यादातर मेहमान सो रहे थे। आग की लपटें दूसरी मंज़िल तक फैल गईं, जबकि घने धुएं ने इमारत के ऊपरी हिस्सों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कई मेहमान अपने कमरों में फंस गए। इस घटना में नौ लोगों की मौत हो गई, जिनमें मेघालय के एक परिवार के 5 सदस्य भी शामिल थे। पुलिस ने होटल के मालिक कल्याण पाल समेत दो लोगों को हिरासत में लिया है। यह कार्रवाई होटल में आग से सुरक्षा नियमों के संभावित उल्लंघन की जांच के तहत की गई है।

जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान नई दिल्ली करेगी, न कि वॉशिंगटन

-सर्जियो के साथ बैठक से पहले सीएम उमर बोले- दूसरे से शिकायत करना गलत

जम्मू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर के साथ बैठक से पहले एक साफ कूटनीतिक दायरा तय किया और अटकलों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर की समस्याओं का समाधान नई दिल्ली करेगी, न कि वॉशिंगटन। बुधवार सुबह श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने साफ किया कि हालांकि वह स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन वह इस बैठक का इस्तेमाल किसी विदेशी राजनयिक के सामने भारत की शिकायत करने के लिए बिल्कुल नहीं करेंगे।

अब्दुल्ला ने साफ कहा कि वॉशिंगटन हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। हमारी केंद्र सरकार को ही हमारी समस्याओं का समाधान करना होगा। किसी दूसरे देश के राजदूत से शिकायत करना गलत होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि श्रीनगर में अमेरिकी राजदूत के साथ बुधवार को प्रस्तावित बैठक में अंतरराष्ट्रीय मुलाकातों के लिए तय प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उमर ने कहा कि मैं जम्मू-कश्मीर और वहां के हालात के बारे में बात करूंगा, लेकिन शिकायत नहीं करूंगा। मैं उनसे अपनी समस्याओं का समाधान खोजने की कोशिश भी नहीं करूंगा। यह देखते हुए कि 15 से ज्यादा सालों में यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर का कोई मौजूदा सीएम किसी मौजूदा अमेरिकी राजदूत से मिल रहा है। अब्दुल्ला ने कहा कि ज्यादातर, मैं उनकी बात सुनना पसंद करूंगा। हालांकि वह भी सुनने ही आ रहे हैं।

यह हाई-प्रोफाइल मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब जम्मू-कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां राज्य का दर्जा पूरी तरह बहाल करने और संवैधानिक गारंटी की सक्रिय रूप से मांग कर रही हैं, जहां विश्लेषक इस बैठक को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अहम संदेश के तौर पर देख रहे हैं क्योंकि गोर दक्षिण और मध्य एशिया के लिए वॉशिंगटन के विशेष दूत की दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। वहीं सीएम अब्दुल्ला ने अपने संबोधन में विदेशी मध्यस्थता या आंतरिक मतभेदों से जुड़ी किसी भी अटकल को पहले ही शांत करने की कोशिश की।

राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी वाड्रा को हटा दें, तब कांग्रेस में शामिल होऊंगा

पूर्व भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला का बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्व भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने फैसले की वजह खुलकर आर्थिक और व्यक्तिगत कारणों को बताया है, जिसका जिक्र उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू में किया था। हालांकि, भाजपा ने अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है।

पूनावाला ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल अपने कार्यकर्ताओं को कोई वेतन नहीं देते, जबकि उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों जैसे मकान किराया आदि का भुगतान करना होता है। उन्होंने कहा, मेरा मकान मालिक घर इसलिए मुफ्त में नहीं दे देगा, क्योंकि मैं भाजपा से हूं। वहां हर महीने की 1 तारीख को किराया मांगता है। उन्होंने जोड़ा कि किसी राजनीतिक आंदोलन से जुड़ना नौकरी नहीं है, बल्कि यह विचारधारा, व्यक्ति या संगठन के प्रति प्रेम का परिणाम होता है। उन्होंने बताया कि वह 2024 से ही इस्तीफे पर विचार कर रहे थे और इस दौरान कई नेताओं ने उनसे संपर्क भी साधा था।

कांग्रेस में शामिल होने के सवाल पर पूनावाला ने भले ही सीधे इंकार किया हो, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसी शर्तें रखीं जो अवास्तविक लगती हैं। उन्होंने कहा कि वह कांग्रेस में तभी शामिल हो सकते हैं, जब राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को हटा दिया जाए और नेहरू के कार्यों के लिए माफी मांगी जाए। खास बात यह है कि पूनावाला स्वयं 2021 में कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी वैचारिक निष्ठा दिखाकर कहा कि पीएम मोदी से बड़ा नेता इस देश में न कोई हुआ है और न ही कोई होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा इस समय भारत की सबसे अच्छी पार्टी है और राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर काम करने के बाद वह किसी अन्य पार्टी से जुड़ने के बारे में नहीं सोचते। उनके त्याग पत्र में भी आर्थिक मजबूरियों का हवाला देकर मोदी जी के विजन के समर्थन की बात कही गई है।

हरियाणा में अग्निवीरों को तोहफा : 6 सरकारी नौकरियों में 20 प्रतिशत आरक्षण

गुरुग्राम (एजेंसी)। हरियाणा की नायाब सैनी सरकार ने सेना से लौटे अग्निवीरों के लिए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किया है, इसके तहत उन्हें विभिन्न सरकारी नौकरियों में विशेष आरक्षण और भर्ती प्रक्रिया में छूट मिलेगी। यह नई व्यवस्था आगामी 1 सितंबर से लागू होगी, जिसका उद्देश्य सैन्य सेवा और प्रशिक्षण के दौरान प्राप्त कौशल को सम्मान देना और उनके लिए नई राहें खोलना है। सबसे बड़ा लाभ पुलिस कांस्टेबल, वन रक्षक, जेल वार्डर, माइनिंग गार्ड, वन्य जीव गार्ड और फायर ऑपरेटर सह चालक सहित छह महत्वपूर्ण पदों पर मिलेगा, जहाँ अग्निवीरों को 20 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस आरक्षण के अंतर्गत वंचित अनुसूचित जाति (2 प्रतिशत), अन्य अनुसूचित जाति (2 प्रतिशत), बीसी-ए (3 प्रतिशत), बीसी-बी (2 प्रतिशत), ईडब्ल्यूएस (2प्रतिशत) और अनारक्षित श्रेणियों (9 प्रतिशत) के लिए कोटा निर्धारित किया है। इसके अतिरिक्त, अन्य ग्रुप-सी पदों पर पूर्व अग्निवीरों के लिए 5 प्रतिशत और कौशल विशेषज्ञता से संबंधित ग्रुप-बी पदों पर 1 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं पुलिस कांस्टेबल और अन्य संबंधित पदों के लिए आवश्यक फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट (पीएसटी) से उन्हें छूट दी जाएगी। ग्रुप-सी पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) से भी छूट का मौजूदा प्रावधान जारी रहेगा। साथ ही, सैन्य प्रशिक्षण से संबंधित कौशल विशेषज्ञता वाले पदों पर कौशल परीक्षा से भी उन्हें छूट प्राप्त होगी। हालांकि, इन सभी छूटों के बावजूद, विज्ञापित पद के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित लिखित परीक्षा देना पूर्व अग्निवीरों के लिए अनिवार्य रहेगा। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों ने सरकार के पुराने आदेशों को रद्द किया है, इससे अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में एक सुव्यवस्थित और प्राथमिकता आधारित प्रवेश मिल सकेगा।

डीजेबी टेंडर घोटाले में एसीबी ने आप नेता सत्येंद्र जैन को किया गिरफ्तार

-वित्तीय जांच में रिश्वत और कमीशन के पैसे के लेनदेन की श्रृंखला उजागर

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की एंटी करप्शन ब्रांच (एसीबी) ने दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के आधुनिकीकरण में अनियमितताओं और आपराधिक साजिश के मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व जल मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया है। इस मामले में सत्येंद्र जैन के अलावा दिल्ली जल बोर्ड के पूर्व सीईओ व पूर्व आईएएस अधिकारी उदित प्रकाश राय, पूर्व संविदा सलाहकार अंकित श्रीवास्तव और तीन निजी संस्थाओं और कंपनियों के मालिकों नागेंद्र यादव, राजा कुमार कुरर एवं पंकज वर्मा को भी गिरफ्तार किया है। एसीबी प्रमुख एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त विक्रमजीत सिंह के बयान के मुताबिक ये गिरफ्तारियां एफआईआर के बाद की गईं थीं, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पीएस भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जीएनसीटीडी में पंजीकृत है। जांच में सामने आया कि एसटीपी टेंडर प्रक्रिया में तकनीकी शर्तों और नियमों में जानबूझकर फेरबदल किया गया था। टेंडर की शर्तें इस तरह तैयार की गईं, जिससे प्रतिस्पर्धा सीमित हो जाए और एक खास निजी टेक्नोलॉजी प्रदाता कंपनी 'मेसर्स यूरोटेक एनवायरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ पहुंचाया जा सके। जांच अधिकारियों के मुताबिक प्रस्तावित पायलट स्टडी को पूरा न करना, तकनीकी मापदंडों में बदलाव और उपचारित पानी के जरुरी मानकों को हटाना जैसी अनियमितताएं पाई गईं, जिससे सरकारी खजाने को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के विश्लेषण से पता चला है कि टेंडर की शर्तें तय करने और संशोधन जारी करने में निजी व्यक्तियों, बिचौलियों और सरकारी अधिकारियों के बीच नियमित साठगांठ थी, ताकि टेंडर केवल पसंदीदा कंपनी को ही मिले। वित्तीय जांच में रिश्वत और कमीशन के पैसे के लेनदेन की पूरी श्रृंखला उजागर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोटेक कंपनी से जुड़ी संस्थाओं से फंड नागेंद्र यादव की प्रोप्राइटरशिप फर्म 'ए एन एंटरप्राइजेस और 'सृजनहार के जरिये हस्तांतरित किया गया। इस माध्यम से तत्कालीन सीईओ उदित प्रकाश राय और उनके रिश्तेदारों के बैंक खातों में करीब 1.52 करोड़ रुपए की रिश्वत भेजी गई, जिसका इस्तेमाल अचल संपत्ति खरीदने में किया गया। इन सभी दस्तावेजी और तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के बाद एसीबी ने 18 अगस्त 2026 को छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल जांच एजेंसियां अपराध की पूरी कमाई और इस साजिश में शामिल अन्य पहलुओं की जांच कर रही हैं।

अखिलेश चुनाव में हार से बचने कांग्रेस को 300 सीटें देने का बना रहे प्लान

-बीजेपी और एनडीए सहयोगियों ने सपा प्रमुख पर किया जोरदार हमला

लखनऊ (एजेंसी)। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जुबानी जंग जारी है। अखिलेश यादव बीजेपी और एनडीए सहयोगियों- आरएलडी, अपना दल और सुभासपा और निषाद पार्टी पर हमलावर हैं। इस बीच अब बीजेपी ने सपा प्रमुख पर उन्हीं के अंदाज में पलटवार किया है। बीजेपी का दावा है कि अखिलेश चुनाव में हार की जिम्मेदारी से बचने के लिए कांग्रेस को करीब 300 सीटें देने का प्लान बना रहे हैं। इसके अलावा अपना दल नेता आशीष पटेल ने भी सपा पर निशाना साधा है।

बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि अखिलेश के पारिवारिक विवाद ने समाजवादी पार्टी की गुप्त योजनाओं को सार्वजनिक कर दिया है। उन्होंने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि 2027 विधानसभा चुनाव में हार का ठीकरा अपने ऊपर न फूटे, इसलिए सपा कांग्रेस को करीब 300 सीटें सौंपने जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है, ताकि हार का मेडल राहुल गांधी के सिर बंधे और अखिलेश जिम्मेदारी से बच जाएं।

इससे पहले अखिलेश ने बीजेपी और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए सूत्रों के हवाले से एनडीए का सीट बंटवारा फॉर्मूला साझा किया था। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी पीडीए के दबाव में रालोद को 73, सुभासपा को 39, निषाद पार्टी को 31 और अपना दल को 19 सीटें देने की योजना बना रही है। अखिलेश ने कहा था कि यह योजना पीडीए की जनसंख्या अनुपात से बहुत कम है और पूरी तरह विफल साबित होगी।

अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा-परीक्षा घपलों, फर्जी मुकदमों, बुलडोजर कार्रवाई और 69000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण प्रभावित करने जैसी नीतियों से जनता त्रस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना लाने, स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल करने और संविधान बदलने की साजिश करने वालों को जनता नकार चुकी है। उन्होंने नारा दिया कि आज हर जन कह रहा है कि उन्हें बीजेपी नहीं चाहिए।

वहीं, अखिलेश के एनडीए के सीट बंटवारा फॉर्मूले पर अपना दल ने भी पलटवार किया। अपना दल नेता आशीष पटेल ने सपा प्रमुख के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट और रीट्वीट का खेल नहीं खेलती है। वह जमीन पर जनता के बीच काम करने और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास करते हैं। पटेल ने कहा कि एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है और इसी हकीकत से परेशान होकर सपा नेता दूसरों के शब्दों को अफवाह बताते-बताते खुद अफवाहों के वाहक बन रहे हैं।

सारे मंदिर अभी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चोरी की जा सके : रेणुका

नई दिल्ली (एजेंसी)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य रेणुका चौधरी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी, वंदे मातरम विवाद और राजनीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखे सवाल किए। उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी द्वारा चंपत राय को क्लीन चिट देने पर कहा कि ये पहले ही अपेक्षित था कि बड़े लोगों को बचाने के लिए निचले स्तर पर काम कर रहे लोगों को कुर्बान कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था। हमें पहले से पता था कि यही होने वाला है। छोटे-मोटों को कुर्बान कर देंगे और चंपत राय को बचा लेंगे। उन्होंने कहा कि सारे मंदिर अभी इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि चोरी की जा सके। ये भूल गए कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा से खिलवाड़ करेंगे तो ये बच जाएंगे। उनका श्राप इनको ही लगा है। बता दें मंगलवार को अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रही एसआईटी ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के पूर्व सदस्य अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दे दी है। मंदिर में दान के प्रबंधन में अनियमितताओं के आरोप सामने आने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों ने 27 जून को अपने-अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद मंदिर में दान प्रबंधन और संग्रह से संबंधित जांच के लिए एसआईटी ने दोनों से पूछताछ की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वंदे मातरम के पूरे गीत को राजनीतिक और हिंदू-मुस्लिम से जोड़कर देखे जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस समय जो माहौल था, उस कारण से फैसला हुआ था। आज ये लोग किस कारण से कर रहे हैं, वही जानें और भगवान जाने। वैसे तो भगवान राम भी इनसे हटकर बैठे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के भविष्य को लेकर पूछे गए सवाल पर रेणुका चौधरी ने कहा कि एक लोकतंत्र में हम कोई हाथ-ज्योतिषी बनकर नहीं कह सकते हैं।

सीएम विजय का ऐलान: हर विधायक को मिलेगी नई कार

विधायकों की मांग पर टीवीके सरकार का फैसला, क्षेत्र में दौरे और विकास कार्यों की निगरानी में मिलेगी मदद

चेन्नई (एजेंसी)। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) प्रमुख थलपति विजय ने राज्य के सभी विधायकों को यात्रा के लिए नई कार उपलब्ध कराने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लगातार दौरे करने पड़ते हैं और जनता की समस्याओं तथा जरूरतों का जायजा लेने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र में रहना जरूरी है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त लॉजिस्टिक्स और वाहन सुविधा उपलब्ध कराना आवश्यक है।

सरकार का यह फैसला विधानसभा में विधायकों के लिए वाहनों और जरूरी लॉजिस्टिक्स की सुविधा का मुद्दा उठाए जाने के बाद आया है। वीसीके विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में कहा था कि यदि विधायकों को जरूरी संसाधन और वाहन उपलब्ध नहीं होंगे तो वे अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से काम नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सरकार से विधायकों के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था।

मुख्यमंत्री विजय ने विधायक के सुझाव को गंभीरता से लेते हुए सभी विधायकों के लिए नई कार उपलब्ध कराने का निर्णय लिया। सरकार का मानना है कि वाहन सुविधा मिलने से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्रों में अधिक आसानी से पहुंच सकेंगे और जनता से सीधे संवाद के साथ-साथ विकास कार्यों की निगरानी भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।

जनता से संपर्क में आसानी होगी

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सरकार की ओर से सभी विधायकों के लिए वाहनों की व्यवस्था की जाएगी। इससे ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में आने-जाने वाले विधायकों को विशेष सुविधा मिलने की उम्मीद है। विधायक नियमित रूप से अपने क्षेत्र का दौरा कर सकेंगे और सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल तथा अन्य स्थानीय समस्याओं की जानकारी लेकर संबंधित विभागों के साथ उनका समाधान कराने में तेजी ला सकेंगे। विधायक जोतिमणि ने विधानसभा में अपने क्षेत्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए वाहनों को जरूरी सुविधा बताया था। उनके अनुरोध पर मुख्यमंत्री विजय द्वारा लिया गया यह फैसला सरकार और विधायकों के बीच बुनियादी संसाधनों को लेकर उठाए गए मुद्दे के समाधान के रूप में देखा जा रहा है।

आँख की रोशनी गायब, शरीर में छर्रों का दर्द... लेकिन दीपके ने नहीं ली कोई खबर

-संसद मार्च के दौरान घायल हुए छात्रों का दर्द

नई दिल्ली (एजेंसी)। नीट पेपर लीक के खिलाफ हुए संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा को एक महीना पूरा हो चुका है, लेकिन घटना में पैलेट गन के छर्रे लगने से घायल हुए छात्रों के जख्म अभी भी ताजा हैं। पीड़ितों को इस बात की टीस ज्यादा है कि जिस कॉकराच जनता पार्टी (सीजेपी) ने उन्हें समर्थन का आश्वासन दिया था, वह अब उनका हाल भी नहीं पूछ रही है।

नजफगढ़ के छात्र साहिल लोचव की दूसरी सर्जरी के बावजूद दाईं आंख की रोशनी वापस नहीं लौट सकी है। 19 वर्षीय साहिल की आंख में पैलेट के छर्रे लगने से कॉर्निया में छेद हुआ था। उसकी मां ज्योति बताती हैं कि 20 जुलाई की घटना में साहिल की आंख और हाथ में छर्रे लगे थे, जिसमें से सभी अब तक नहीं निकाले जा सके हैं। इससे उसका एक हाथ भी ठीक से काम नहीं कर रहा। एम्स ट्रॉमा सेंटर में आंख की सर्जरी और बाद में लेंस डालने के बावजूद रोशनी नहीं लौटी है। स्नातक द्वितीय वर्ष के छात्र साहिल की पढ़ाई गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और वह अभी भी अस्पताल में भर्ती है।

वहीं मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी इरशाद मंसूरी के चेहरे, आंख के पास, छाती और शरीर के कई हिस्सों में पैलेट गन के करीब 40 छर्रे लगे थे। 21 जुलाई को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में सर्जरी कर कुछ छर्रे निकाले गए, लेकिन कई अभी भी शरीर में मौजूद हैं। गुरुग्राम की कॉरपोरेट कंपनी में कार्यरत इरशाद पूरी तरह स्वस्थ नहीं हुए हैं और घाव नहीं भरने के कारण ड्यूटी जॉइन नहीं कर सके हैं। बिहार के 25 वर्षीय छात्र प्रशांत के हाथ, छाती और कमर में पैलेट के छर्रे लगे थे, जिससे उनका दायां हाथ कुछ समय के लिए सुन्न पड़ गया था। डॉक्टरों ने कुछ छर्रे निकाले, लेकिन कई छोटे छर्रे मांसपेशियों में गहराई तक धंसे हैं, जिन्हें निकालने से और अधिक घाव होने का डर है। प्रशांत अब नौकरी की तैयारी करते हुए भी पहले जैसा सामान्य महसूस नहीं कर रहे हैं। साहिल की मां और प्रशांत दोनों ने बताया कि घटना के बाद से सीजेपी की तरफ से किसी ने उनसे संपर्क नहीं किया है। जख्मी प्रदर्शनकारियों में अब यह कड़वाहट साफ दिखती है कि राजनीतिक दल ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया है।

शहबाज शरीफ की परमाणु धमकी और ट्रंप की चुप्पी पर भड़के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल

नई दिल्ली (एजेंसी)। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार की जा रही प्रशंसा और दक्षिण एशिया में परमाणु तबाही टलने का श्रेय देने के मामले पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बल ने कड़ी आपत्ति जाहिर की है। पूर्व विदेश सचिव सिब्बल ने शहबाज शरीफ पर निशाना साधकर कहा कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहबाज ट्रंप के बढ़े हुए अहंकार को खुश करने और राजनीतिक समर्थन हासिल करने के लिए चापलूसी में लगे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शहबाज इस मामले में अति कर रहे हैं और ट्रंप को वहीं बातें बता रहे हैं जो वे सुनना पसंद करते हैं।

शरीफ ने पोस्ट कर ट्रंप के नेतृत्व की सराहना कर दावा किया था कि उनके साहसी कदमों से दक्षिण एशिया में परमाणु तबाही टली और लाखों लोगों की जान बच गई। हालांकि, पूर्व विदेश सचिव सिब्बल ने बयान के गंभीर निहितार्थों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उनका कहना है कि शहबाज के इन बयानों में भारत के विरुद्ध परमाणु हथियारों के संभावित पहले इस्तेमाल का छिपा हुआ संकेत और आक्रामक धमकी शामिल है। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया न आना चिंता का विषय है।

पूर्व विदेश सचिव ने अमेरिका के रवैये को पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जिस प्रकार परमाणु हथियारों को लेकर बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर अमेरिकी नेतृत्व की चुप्पी या अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसतरह के बयानों को नजरअंदाज करना अंतरराष्ट्रीय शांति के हित में नहीं है।

इसके अतिरिक्त, शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब और तुर्किये के साथ हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते का भी उल्लेख कर इसके लिए अमेरिकी समर्थन का आभार जताया। ट्रंप ने इस त्रिपक्षीय समझौते को एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। बहरहाल, पाकिस्तान की परमाणु बयानबाजी और उस पर अमेरिकी प्रशासन की चुप्पी को लेकर सिब्बल के इन तीखे बयानों ने कूटनीतिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है।